दैनिक

सांध्य प्रकाश

भोपाल की धड़कन

वर्ष 55/ अंक 10/ पृष्ठ 8 / मूल्य ₹2.10 संस्थापक- स्व. सुरेंद्र पटेल ■आर.एन.आई 22296/71 ■डाक पंजीयन मप्र/भोपाल/125/12-14

भोपाल, शुक्रवार 25 जुलाई 2025 भोपाल से प्रकाशित dainiksandhyaprakash.in

सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 81,470 पर आया, निफ्टी 250 अंक लुढ़का

मुंबई। शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 700 अंक गिरकर 81,470 के स्तर पर कारोबार आ गया। निफ्टी में करीब 250 अंक की गिरावट है, ये 24,820 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 3 में तेजी और 27 में गिरावट है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर्स 5.3% और 4.2% गिरे हैं।

मालदीव में मोदी का भव्य स्वागत

स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि

माले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्रिटेन यात्रा के समापन के बाद शुक्रवार को मालदीव पहुंचे। इस दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू समेत मालदीव के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री ने वेलाना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए माले में एयरपोर्ट पर बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने ताली बजाते हुए बाल कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी इन बाल कलाकारों से मिलने उनके बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के मालदीव पहुंचने पर प्रवासी

भारतीय नागरिकों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के बाहर मौजूद इन प्रवासी नागरिकों से मुलाकात की। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर घंटे भारतीय नागरिकों ने 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। यह उनका तीसरा मालदीव दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी साल 2018 और 2019 में मालदीव गए थे। उनकी उपस्थिति भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है।

सैंड्रिंघम हाउस में मोदी की एंट्री, पहली बार किसी भारतीय नेता ने रखा कदम

लंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ब्रिटेन यात्रा कई प्रतीकात्मक और रणनीतिक उपलब्धियों से भरी रही, लेकिन एक घटना ने विशेष ध्यान आकर्षित किया – उनका 'सैंड्रिंघम पैलेस' पहुंचना। यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस अत्यंत निजी और ऐतिहासिक शाही निवास में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। खुद राजा चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के संबंधों की बदलती प्रकृति का

स्पष्ट संकेत है। सैंड्रिंघम हाउस, इंग्लैंड के नॉरफोक काउंटी में स्थित एक विशाल शाही संपत्ति है, जिसे ब्रिटिश राजपरिवार के निजी अवकाश स्थल के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में प्रिंस अल्बर्ट (बाद में किंग एडवर्ड 7) के लिए खरीदे गए इस एस्टेट का क्षेत्रफल लगभग 8000 एकड़ है, जिसमें वन, जलाशय, कृषि-भूमि और एक ऐतिहासिक चर्च शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सैंड्रिंघम में स्वागत केवल एक प्रोटोकॉल से अधिक है – यह एक राजनयिक संकेत है कि ब्रिटेन भारत को पारंपरिक संबंधों से आगे बढ़कर अब सांस्कृतिक और भावनात्मक निकटता के दायरे में देख रहा है। इस अवसर पर राजा चार्ल्स ने प्रधानमंत्री मोदी की 'एक पेड़ मां के नाम' पहल का समर्थन करते हुए सैंड्रिंघम एस्टेट में एक विशेष पेड़ लगाने की घोषणा की।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन का किया लोकार्पण

हेल्थ सेक्टर में मप्र बन रहा मॉडल: मोहन

भोपाल। गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित हमीदिया अस्पताल अब अत्याधुनिक जांच सुविधाओं से लैस हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को यहां एमआईआर और सिटी स्कैन मशीनों का शुभारंभ किया। यह पहल मध्यप्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सबसे पहले भोपाल से शुरू की गई है।

लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का हेल्थ सिस्टम अब पूरी तरह सरकारी तकनीक पर आधारित होकर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश अब हेल्थ सेक्टर में देश के लिए मॉडल बन रहा है। सीएम ने बताया कि 40 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में एयर एंबुलेंस, मॉडर्न जांच मशीनें और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पीपीपी मॉडल के तहत 4 मेडिकल कॉलेज पहले ही निजी संचालन में सौंपे जा चुके हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

मरीजों को अब मुफ्त मिलेगी जांच सुविधा– हमीदिया अस्पताल में लगी इन मशीनों के जरिए अब आयुष्मान भारत योजना और अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े मरीजों को एमआईआर (1.5 टेसला) और सिटी स्कैन (128 स्लाइस) की जांच पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इससे पहले मरीजों को निजी सेंटर्स पर जाकर भारी खर्च उठाना पड़ता था। अब गंभीर मरीजों की तत्काल जांच अस्पताल परिसर में ही हो सकेगी।

UG-PG छात्रों को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण– इन मशीनों की स्थापना से न केवल मरीजों को लाभ होगा, बल्कि मेडिकल छात्रों को भी प्रैक्टिकल और रिसर्च के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह पहल नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) के नए नियमों के तहत की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों को जांच सुविधाएं स्वतंत्र रूप से संचालित करने का निर्देश है। इन मशीनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित रिसर्च की भी सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश में मेडिकल रिसर्च को नई दिशा मिलेगी।

सर्वाधिक समय पीएम रहने के मामले में मोदी ने इंदिरा को पछाड़ा, नेहरू से अब भी पीछे

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी 25 जुलाई यानी आज तक लगातार सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब तक लगातार सबसे लंबी अवधि (16 वर्ष 286 दिन) तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जवाहर लाल नेहरू के पास है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लेंगे। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहीं। अगर राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकार का नेतृत्व करने की बात करें, तो नरेंद्र मोदी सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक विशेष रिकॉर्ड भी अपने नाम रखते हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कुल 24 सालों तक शासन किया है।

देश की स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री– नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। वो सबसे लंबे वक्त तक सेवा देने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। इसके अलावा, वो पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हैं। उनके नाम लगातार दो बार चुने जाने वाले पहले और अकेले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है।

मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों के खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, संगठन ने तैयार की दावेदारों की अंतिम सूची

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के निगम, मंडल और बोर्डों में 40 से अधिक पद लंबे समय से रिक्त हैं। इन पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी बीते डेढ़ साल से चल रही थी, जिसे अब अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर इन पदों के लिए उपयुक्त नामों की सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही इन पर राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी और नामों की आधिकारिक घोषणा भी होगी।

सीएम हाउस में हुई अहम बैठक, केंद्र से मिल चुकी है मंजूरी– गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में निगम-मंडलों में की जाने वाली नियुक्तियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इन नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार से भी हरी झंडी मिल चुकी है। अब जल्द ही नामों को अंतिम मुहर लगाकर सूची सार्वजनिक की जाएगी।

नए चेहरों को मिलेगा मौका जनभागीदारी समितियों में भी होगी तैनाती

संगठन की मंशा है कि इस बार नियुक्तियों में नए और युवा चेहरों को भी शामिल किया जाए ताकि संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो सके। कॉलेजों की जनभागीदारी समितियों और नगरीय निकायों में एल्डरमैन पदों पर भी नियुक्तियों की तैयारी की जा रही है। इन पदों के लिए अलग से नाम तय किए जा चुके हैं।

सांध्यप्रकाश विशेष

ओला-उबेर को टक्कर देने आ रही सहकार टैक्सी, शहरों में जल्द शुरू होगी सहकारी सेवा

नई दिल्ली। भारत सरकार अब टैक्सी सेवाओं के क्षेत्र में एक नई पहल के साथ प्रवेश करने जा रही है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई राष्टीय सहकारिता नीति-2025 के उद्घाटन के दौरान घोषणा की कि देश में इस वर्ष के अंत तक सहकारिता मॉडल पर आधारित टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा न केवल ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि यात्रियों को भी किफायती और पारदर्शी राइडिंग विकल्प देगी। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ÷सहकार से समृद्धि÷ विजन के तहत तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य सहकारी ढांचे के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

हिम्मत है तो बिहार चुनाव का बहिष्कार करके दिखाए विपक्षः पासवान

पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. जब उनसे पूछा गया कि क्या

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, तो चिराग ने दो टूक कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हिम्मत हो तो एक बार चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। लेकिन, वे कभी ऐसा नहीं करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऐसा करने की ताक़त उनमें नहीं है। चिराग ने यह भी साफ किया कि वे इस बार चुनाव में जनरल सीट से लड़ेंगे, और पूरे दमखम से मैदान में उतरेंगे। बातचीत के दौरान चिराग ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राज्य में कानून का राज होना चाहिए, न कि अपराधियों का।

एसीएस मंडलोई ने राजौरा से मांगे 33.79 करोड़ बिजली बकाया न दिया तो केंद्र का अनुदान लोन में कन्वर्ट होगा, कोयला सप्लाई पर भी असर

भोपाल। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग नीरज मंडलोई ने जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा से 33.79 करोड़ रुपए मांगे हैं। राजौरा से यह राशि प्रदेश की तीनों ही विद्युत वितरण कंपनियों के जल संसाधन विभाग पर बकाया राशि चुकाने के लिए मांगे गए हैं।

साथ ही कहा गया है कि समय पर बिल न चुकाने से आरडीएसएस में

केंद्र से मिलने वाला अनुदान लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं, पेमेंट न होने से कोयले की आपूर्ति पर भी असर पड़ने की बात कही गई है। सबसे अधिक बकाया राशि 16. 29 करोड़ रुपए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में है। राजगढ़ जिले से जल संसाधन विभाग को सबसे अधिक 4.55 करोड़ रुपए चुकाना है। एसीएस मंडलोई ने पत्र लिखकर कहा है कि बिजली कंपनियों द्वारा जल संसाधन विभाग के दफ्तरों और अन्य जल संरचनाओं के लिए कनेक्शन दिए गए हैं। इन बिजली कनेक्शनों की बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है। नियमित भुगतान नहीं किए जाने से यह बकाया राशि मई 2025 की स्थिति में बढ़कर 33.79 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा बिजली लाइन लॉस कम करने के लिए रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत 60 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। इसमें प्रावधान है कि सभी सरकारी विभागों और संबद्ध कार्यालयों व स्थानीय निकायों से बिजली बिल वितरण कंपनियों को भुगतान कराया जाए।

शिक्षा के मंदिर में पसरा मातम

स्कूल बिल्डिंग गिरी सात बच्चों की मौत

पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, सीएम हादसा स्थल जाएंगे

जयपुर एजेंसी। राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार सुबह एक प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा हो गया। पिपलोदी प्राथमिक विद्यालय की इमारत की छत अचानक गिर गई इस घटना में करीब 20 से अधिक बच्चे मलबे में दबे होने का अनुमान है। वहीं छह बच्चों के मौत की जानकारी सामने आई है। हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये हैं।। आशंका जताई जा रही है कि कुछ बच्चे अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। यह हृदय विदारक घटना उस समय

हुई जब बच्चे अपनी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे। पीएम मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहन दुख व्यक्त किया है।

बचाव अभियान जारी, 17 छात्र घायल: घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया। मलबे में फंसे बच्चों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस स्थानीय निवासी और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत कार्यों में जुट गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस दुखद घटना में कुल 17 छात्र घायल हुए हैं।

ग्वालियर में विधानसभा स्पीकर के बंगले में पानी भराया 24 घंटे में 3.7 इंच बारिश

भोपाल। ग्वालियर में सुबह तेज बारिश हुई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सरकारी बंगले में पानी भर गया। भोपाल में कभी धीमी, कभी तेज बारिश हो रही है। प्रदेश में शुक्रवार को 19 जिलों में अति भारी और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इससे पहले गुरुवार को अशोक नगर जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में 26 साल का युवक और ढाई साल का बच्चा बह गए थे। शुक्रवार सुबह उनके शव मिले।

भोपाल में बढ़ते नशे के खिलाफ कांग्रेस ने किया गया प्रदेर्शन

कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर भोपाल में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स तथा लगातार बढ़ रही ड्रग्स की सप्लाई एवं नशे के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे।

भारतीयों से क्यों डरे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जो कह रहे- भारतीयों को न रखें गूगलऔर मेटा

वाशिंगटन। अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट से कहा कि वे भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना और वहां के वर्कर्स को हायर करना बंद करें। ट्रंप का यह बयान भारतीय टैलेंट के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिर भारतीयों से क्यों नाराज हैं अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्प? भारतीयों को वीजा, नौकरी और दूसरे अवसर देने के लिए क्यों मना कर रहे हैं?

दरअसल चिढ़ इंडियन इज द बेस्ट से है– डोनाल्ड ट्रम्प की चिढ़ का असली कारण है- बुरी से बुरी परिस्थिति में भी भारतीयों द्वारा बेहतर काम करके दिखा देने की प्रतिभाज्कोई 52 लाख से ज्यादी भारतीय इस समय अमेरिका में रहते हैं। ये भारतीय हर फील्ड में दूसरों से बेहतर कर रहे हैं। वे दूसरे समुदायों से ज्यादा पढ़े- लिखे हैं। दूसरों से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। और हां! अपनी मेहनत और प्रतिभा की बदौलत दूसरे किसी भी एशियाई समुदाय से ज्यादा कमाते भी हैं। तो फिर कोई हमसे क्यों न चिढ़े चलिए देखते हैं, अमेरिका में भारतीय कैसे धमाल मचा रहे हैं।

भारतीय मूल के प्रमुख सीईओ – आज अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के प्रमुख भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें अल्फाबेट (गूगल) के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला, फेडएक्स के राज सुब्रमण्यम, और टेस्ला के सीएफओ वैभव तनेजा जैसे नाम शामिल हैं। इन कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण करीब 552 लाख करोड़ है। इसके अलावा, अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में सूचीबद्ध टॉप 300 फर्म्स में 61त्न कंपनियां भारतीय मूल के सीईओ या बोर्ड मेंबर्स द्वारा संचालित हो रही हैं, जिनमें से 23त्न कंपनियों की कमान भारतीय मूल की महिलाओं के हाथों में है।

भारतीय नेतृत्व क्षमता– ग्लोबल एडवाइजरी फर्म जीएचस्मार्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, भारतीय मूल के अधिकारियों की क्षमता बाकी से पांच गुना ज्यादा मानी जाती है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि भारतीय नेताओं में जोखिम लेने की क्षमता पांच गुना अधिक है और वे चुनौतियों का सामना करने में भी छह गुना अधिक सक्षम होते हैं। साथ ही, वे जटिल परिस्थितियों में भी परिवर्तन लाने के लिए बेहतरीन नेतृत्व क्षमता रखते हैं।

अमेरिका में भारतीयों के बारे में खास बातें

- भारतीय अमेरिकियों की संख्या एशियाई मूल के लोगों में दूसरी सबसे बड़ी है और यह कुल अमेरिकी एशियाई आबादी का लगभग 21 प्रतिशत है।
- 2000 से 2023 के बीच भारतीय आबादी में लगभग 31 लाख की वृद्धि हुई, जो 174% की बढ़त दर्शाती है।
- 2023 में भारतीय आबादी का 66% प्रवासी हैं, जो 2000 में 73% था। प्रवासियों की कुल संख्या इस दौरान 13 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई है।
- 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 84त्न भारतीय अंग्रेजी बोलने में दक्ष हैं। इनमें से 28% केवल अंग्रेज़ी बोलते हैं, जबकि 56% अन्य भाषा बोलते हुए भी अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो अमेरिका में रहने वाले सभी एशियाई लोगों में से 78 फीसदी भारतीय अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं।
- अमेरिकी भारतीयों के बीच हिंदी (18%), तेलुगु (11%), गुजराती (10%) और तमिल (7%) घर में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाएं हैं।

चंदन वाला ग्रुप ने शिक्षण सामग्री का वितरण किया

भोपाल। लक्ष्मी मंडी हायर सेकंडरी स्कूल में चंदन वाला ग्रुप ने लगभग 250 विद्यार्थियों को कॉपी, पेन, किताबें, रामायण, इरेज़र आदि शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम ग्रुप अध्यक्ष कल्पना जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष कल्पना के एल जैन पूर्व अध्यक्ष सुधा कला सिम्मी संजय वंदना आदिश्वर अल्पना ममता श्रद्धा रिया अर्चना सुनीता स्वति जैन आदि उपस्थित थे।

राजस्व के न्यायालयीन और गैर-न्यायालयीन कार्य प्रणाली का प्रमुख सचिव ने जबलपुर में लिया जायजा

भोपाल। प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल ने गुरुवार को जबलपुर जिले के गोरखपुर तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने नये सेटअप में जिले में राजस्व न्यायालयीन एवं गैर न्यायालयीन कार्यों के लिये नियुक्त अलग-अलग राजस्व अधिकारियों की कार्य प्रणाली को देखा। जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में पूर्णकालिक न्यायिक कार्य करना प्रारंभ हो गया है इसमें अब पीठासीन अधिकारी राजस्व न्यायालयों में कार्य दिवसों में प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक न्यायिक कार्य कर रहे हैं।

पोरवाल ने कहा कि नवीन व्यवस्था निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, जिससे प्रकरणों के निराकरण में सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे और प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण होगा। इससे पहले राजस्व अधिकारियों को बहुत से प्रशासनिक कार्यों के कारण कोर्ट में बैठने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था, अब नई व्यवस्था के तहत न्यायालयों में पूर्णकालिक राजस्व मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। प्रमुख सचिव श्री पोरवाल ने निरीक्षण के दौरान तहसीलदार कोर्ट, अतिरिक्त तहसीलदार कोर्ट की कार्यप्रणाली को देखा। राजस्व अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ नए सेटअप के संबंध में चर्चा कर इसे और बेहतर बनाने के सुझाव भी लिए। इस दौरान कलेक्टर जबलपुर श्री दीपक सक्सेना भी मौजूद थे।

तेरी चढ़ती जवानी गाने ने बढ़ा दिया पुलिस का पारा, इस वायरल रील से प्रशासन के होश उड़े

रीवा। जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र से एक और विवादित घटना सामने आई। पुलिस कस्टडी में ले जाए गए दो वारंटियों ने हथकड़ी पहनने के बावजूद, पुलिस वाहन में मोबाइल से सोशल मीडिया पर एक रील बनाकर उसे वायरल कर दिया। यह रील तेरी चढ़ती जवानी मेरा पारा गोरी गाने पर

आधारित थी। इस घटना में पुलिसकर्मी पूरी तरह से लापरवाह नजर आए, क्योंकि उन्होंने न तो आरोपियों की गतिविधियों पर ध्यान दिया और न ही सुरक्षा नियमों का पालन किया। यह घटना सुरक्षा उल्लंघन का उदाहरण है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में बदमाशों के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचा, यह सवाल खड़ा होता है। इससे पहले भी जिले में 22 मई 2025 को एक हत्या के आरोपी ने अस्पताल में मेडिकल चेकअप के दौरान एक रील बनाई थी। दोनों घटनाओं में पुलिस की चूक और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से देखा गया है।

सगा सग्गुम संस्था जिला संयोजन समिति ने मनाया जीवति पडडुम

भोपाल। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सगा सग्गुम आदिम सामाजिक संस्था भोपाल मप्र इंडिया के तत्वावधान में जिला संयोजन समिति गढ़ भोपाल ने जनजाति समुदाय की मौलिक परंपरा को जीवित रखने की एक सराहनीय कदम उठा रही है कोयापुनेमी जीवति पडडुम बारिश के समय की फसल उत्सव और इस समय उत्तपन्न जीव-जंतु और वनस्पतियों के सम्मान में जनजाति समुदाय पुरातन काल से हर्षोल्लास के साथ यह पर्व को मनाते आ रही है जिसे जनजाति समुदाय की मूल भाषा में कोयापुनेमी जीवा जावा जाड़ी जीवति कहते है इसके उपलक्ष्य में संयोजन समिति द्वारा बरखेड़ा स्थित गौरा गुड़ी पेन ठाना में गोंगो (पूजा) का आयोजन किया गया समिति के अध्यक्ष तिरुमाल - जगदीश मसराम जी के नेतृत्व में यह पर्व में गोंगो समिति के सदस्य तिरुमाल- यशवंत कुर्वेतीद्वारा पेन(देव) पट्ठाओं का विधिवत गोंगो (पूजा) किया गया जिसमें संस्था एंव समिति से जुड़े हुए पदाधिकारियों एंव सदस्यों और नन्हे-मुन्हे कोया पुंगारों (बच्चों) की उपस्थिति रही गोंगो के पश्चात बच्चों द्वारा जीवति पडडुम (पर्व) का मुख्य प्रतीक गेड़ी बांधकर इस पर्व का लुत्फ उठाया और अंत में उपस्थित सभी ने पेन पट्ठाओं एंव एक- दूसरे का सेवा जोहार के साथ अभिवादन कर तिरुमाल - आरपी गोंड़ के द्वारा आभार करके कार्यक्रम स्थागित की ।

एमपी सुपर 100 योजना

इंजीनियरिंग-नीट के लिए मुफ्त कोचिंग, कल तक करें आवेदन, 3 अगस्त को होगी परीक्षा

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की सुपर 100 योजना के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं (जेई,नीट) की तैयारी कर रहे मेधावी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग, हॉस्टल, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल लैब और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इच्छुक छात्र 26 जुलाई शनिवार तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रवेश के लिए रविवार, 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में स्थित उत्कृष्ट स्कूलों में होगी। परीक्षा शुल्क 200 रुपये रखा गया है, जो पंजीकरण के समय जमा करना होगा। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को भोपाल के सरकारी सुभाष उच्चतर माध्यमिक स्कूल

और इंदौर के सरकारी मल्हार आश्रम उच्चतर माध्यमिक स्कूल में विशेष कोचिंग क्लासेस करवाई जाएंगी। छात्रों को यहाँ निशुल्क आवास (हॉस्टल), स्मार्ट क्लासरूम्स, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (मॉडर्न लैब), वर्चुअल क्लास और करियर काउंसलिंग की सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही छात्रों को देश के टॉप इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिला पाने में सहयोग भी मिलेगा।

परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था- राज्य सरकार ने परीक्षा केंद्रों को सभी जिलों के उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित किया है, ताकि विद्यार्थियों को अपने ही जिले में परीक्षा देने की सुविधा मिल सके। परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन होगी और निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी।

कैसे करें आवेदन?

छात्र www. mponline. gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा से जुड़े एडमिट कार्ड www.mponline.gov.in वेबसाइट या MPSOS मोबाइल एप के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकते हैं। योजना, परीक्षा या आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए छात्र फोन नंबर 0755-2552106 पर संपर्क कर सकते हैं। इससे उन्हें आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। मध्यप्रदेश सरकार की यह पहल न सिर्फ मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करती है, बल्कि उन्हें आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर उनके भविष्य को नई दिशा देती है। इच्छुक विद्यार्थी समय रहते आवेदन जरूर करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं।

''साथी हाथ बढ़ाना'' कैंपेन के तहत ग्वालियर में सांची दूध और दूध उत्पादों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता अभियान शुरू

ग्वालियर। एमपी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) भोपाल से संबद्ध ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा ग्वालियर शहर में ''साथी हाथ बढ़ाना'' कैंपेन के तहत उपभोक्ता जागरूकता अभियान 23 जुलाई से प्रारंभ किया गया है। इस कैंपेन के तहत ग्वालियर शहर में ओएसडी एनडीडीबी श्री दिव्य शर्मा नई दिल्ली एवं ग्वालियर दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मोहम्मद राशिद की उपस्थिति में विपणन दल द्वारा सांची कैनोपी लगाकर उपभोक्ताओं को सांची दूध, दूध उत्पादों सहित सांची घी के बारे में अवगत कराया तथा दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित दूध, दुग्ध उत्पाद और घी की जानकारी पम्मलेट वितरित करके प्रदाय की गई। उपभोक्ताओं द्वारा इस अभियान की काफी सराहना की जा रही है। ग्वालियर दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ''साथी हाथ बढ़ाना'' कैंपेन आगामी दिनों में भी दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के शहरों के विभिन्न स्थलों और हाउसिंग सोसाइटी में नियमित चलाई जाएगी।

युवाओं ने संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग को मांगों का ज्ञापन सौंपा

भोपाल। न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बावजूद डिप्लोमा धारकों को सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद पर नियुक्ति न दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा । मध्यप्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ द्वारा स्पष्ट और अंतिम आदेश पारित किए जा चुके हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्यता 6 फरवरी 2012 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पशुपालन मंत्री अजय विश्नोई द्वारा नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा संस्थान, जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 डिप्लोमा कॉलेजों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक कॉलेज में 60 सीटें थीं, कुल 300 सीटें।

आज तक डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र वर्ष 2012 से अब तक लगभग 5500 छात्र डिप्लोमा उत्तीर्ण कर चुके हैं। इस कोर्स को करने वाले छात्र ज़्यादातर ग्रामीण और मध्य वर्गीय परिवार से आते है। चूंकि डिप्लोमा होल्डर्स का पंजीकरण शासन द्वारा नहीं किया जाता इसलिए डिप्लोमा होल्डर्स अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, ऐसे में डिप्लोमा होल्डर्स के पास कैरियर विकल्प बहुत सीमित है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद एक मात्र पद है जिसके द्वारा डिप्लोमा होल्डर्स शासकीय सेवा में आ सकते हैं। न्यायालयीन आदेशों का क्रमः याचिका क्रमांक 19468/2019 उच्च

न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की गई। 3/12/2020 को उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश देते हुए, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद पर डिग्री धारी की नियुक्ति याचिका क्रमांक 19468/2019 के अंतिम फैसले के अधीन रखा गया।याचिका क्रमांक 19468/2019 उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा दिनांक 10.03.2025 को सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद पर डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ डिग्रीधारियों द्वारा डबल बेंच में याचिका क्रमांक 1642/2025 दाखिल की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 16.05.2025 को खारिज कर दिया गया।

पशुपालन विभाग द्वारा पुनः डबल बेंच में याचिका क्रमांक 1727/2025 दाखिल कि गई, इस अपील को भी 03.07.2025 को खारिज कर दिया गया और याचिका क्रमांक 19468/2025 में दिनांक 10/3/2025 को पारित आदेश को मान्य किया गया। उपरोक्त सभी न्यायिक आदेशों के बावजूद विभाग अभी तक न तो नई चयन सूची निकाल रहा है और न ही डिप्लोमा धारकों को उनका न्यायोचित हक दे रहा है, साथ ही उन डिग्री धारी की नियुक्ति निरस्त नहीं कर रहा है, जिनकी नियुक्ति माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन थी। विभाग अपनी मनमानी से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, जो न केवल निंदनीय है, बल्कि कानून का उल्लंघन भी है। एक डिप्लोमा छात्र के प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा 2 वर्षों में आरएस2,40,000 की राशि व्यय की जाती है। इसके बाद भी यदि उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती, तो यह सरकार के संसाधनों की अनुचित बर्बादी और छात्रों के साथ अन्याय है। युवाओं की मांगें हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 19468/2019 (दिनांक 10.03.2025) को शीघ्र लागू किया जाए। डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति सूची शीघ्र जारी की जाए। जिन डिग्री धारी की नियुक्ति माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन थी, उनकी नियुक्ति निरस्त कर, उनकी जगह डिप्लोमा धारको की नियुक्ति की जाए। विभागीय अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेशों की उपेक्षा करने की जवाबदेही तय की जाए। भविष्य में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पदो पर नियुक्ति भर्ती नियम और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप डिप्लोमा धारकों को ही दी जाए।

यशोदा पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद के चुनाव पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से सम्पन्न हुए

संत हिरदाराम नगर। यशोदा पब्लिक स्कूल गांधीनगर में आयोजित छात्र परिषद के चुनाव में सभी विद्यार्थियों ने अपने वोट का प्रयोग करते हुए अलग-अलग पदों हेतु विद्यार्थियों का चुनाव किया। चुनाव के दौरान सभी विद्यार्थियों को लोकतंत्र के महत्व के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है ये भी विस्तार से बताया गया। चुनाव पूरे विधि विधान से सम्पन्न हुए इसमें बच्चों द्वारा नामांकन से लेकर नाम वापस लेने की प्रक्रिया, चुनाव प्रचार, वोट डालने हेतु मतदाता सूची एवं बच्चों की उंगली पर स्याही लगाना आदि शामिल था। चुनाव में प्रियांश नामदेव अध्यक्ष, दीपशिखा महोबिया उपाध्यक्ष, सचिव प्रियंका नामदेव, सांस्कृतिक सचिव लक्ष्मी मालवीय, मनोरंजन सचिव रितिका कामले, अनुशासन सचिव चंदा झनके, खेल सचिव आर्यन राठौर, स्वच्छता सचिव सिद्धार्थ सरदार, प्रार्थना सचिव विराट बाघरी के रूप में चुना गया। स्कूल के सभी स्टाफ ने मिलकर चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराई।

रुद्राभिषेक अनुष्ठान

अनुष्ठान के समापन दिवस तक 11 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर किया विधिवत रुद्रमहाभिषेक

संत हिरदाराम नगर। संत नगर ओल्ड डेरी फार्म स्थित शिव दुर्गा मंदिर पर हर साल की तरह साल भी श्रावण मास के अवसर पर चल रहे पंच दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण के अनुष्ठान कार्यक्रम का गुरूवार को समापन किया गया। श्रद्धालुओं ने समापन दिवस तक 11 लाख से अधिक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन और रुद्रमहाभिषेक किया। गुरूवार को श्रद्धालुओं ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लाखों की संख्या में पार्थिव शिवलिंग बनाए और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक अभिषेक और पूजन किया। विद्वान ब्राहम्णों द्वारा यह पूजन सम्पन्न करवाई गई। इस अवसर 12 ज्योर्तिलिंग की भव्य झांकी के दर्शन भी श्रद्धालुओं को कराए गए। समापन के बाद सभी शिवलिंगों को जल में विसर्जित किया गया। कार्यक्रम आयोजक पंडित प्रमोद चौबे ने कहा कि जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, वही लोग ऐसे दिव्य और भव्य आयोजनों में सम्मिलित हो पाते हैं। यह सब भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा का ही परिणाम है कि इस अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर 11 लाख मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत पूजन और अभिषेक किया। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व का भी वर्णन किया और बताया कि हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जीवन का कल्याण होता है और इनका स्मरण भी पुण्य देने वाला होता है।

साधु वासवानी स्वशासी महाविद्यालय ने स्कोप ग्लोबल स्किल से किया एमओयू समझौता

संत हिरदाराम नगर। साधु वासवानी स्वशासी महाविद्यालय द्वारा स्कोप ग्लोबल स्किल विश्वविद्यालय भोपाल के साथ समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के माध्यम से महाविद्यालय के छात्र -छात्राएं स्किल ग्लोबल विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न प्लेटफार्म एवं मॉडल्स पर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एवं सर्टिफिकेट कोर्स के अवसर प्राप्त कर सकते है। साथ ही छात्र-छात्राएं विभिन्न शार्ट टर्म कोर्स के माध्यम से अपनी स्किल को बढ़ाकर रोजगार प्राप्त कर सकते है। इस अवसर पर साधु वासवानी महाविद्यालय की ओर से साधु वासवानी एल्यूकेशनल सोसायटी के अध्यक्ष दयालदास डेटानी, महाविद्यायल के प्राचार्य डॉ. अनिल सिंह, ऐडमिनिर्स्ट्रेटिव डायरेक्टर डॉ. डी.के. दुबे, एकेडमिक डायरेक्टर डॉ. सुमन मलिक, आई.क्यू.ए.सी. संयोजक डॉ. मणी शुगानी, ऑटोनोमस कंट्रोलर डॉ. अनुपम सेलट, यू.जी.सी. संयोजक डॉ. हिना आसवानी तथा स्कोप ग्लोबल युनिर्वसिटी की ओर से एजीएम आशीष सूद, प्रभाकर सिन्हा व एग्जीकेटिव महिमा मालवीय उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश में स्कूलों की बदहाली उजागर करने NSUI का

प्रदेशव्यापी स्कूलों की पोल खोल अभियान लॉन्च

भोपाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यू-डाइस डेटा और हाल ही में हुई पीएबी बैठक में प्रस्तुत राज्य रिपोर्ट ने मध्यप्रदेश की स्कूली शिक्षा की भयावह स्थिति को उजागर किया है। एनएसयूआई मध्यप्रदेश द्वारा एक प्रदेशव्यापी अभियान स्कूलों की पोल खोल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की जमीनी सच्चाई को सामने लाना और बच्चों के भविष्य से हो रहे मज़ाक पर सरकार से जवाब माँगना। इस अभियान के तहत संगठन ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर छात्र, अभिभावक और जागरूक नागरिक अपने क्षेत्र

के स्कूलों की तस्वीरें, वीडियो और समस्याएं भेज सकते हैं। ये सभी तथ्य एकत्र कर सरकार को घेरने और शिक्षा बजट के सही उपयोग की माँग को लेकर दबाव बनाया जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर इस अभियान की औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ नाम बदलने में व्यस्त है, ज़मीन पर बच्चों के सिर पर ढंग की छत तक नहीं है। 12,200 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक हैं, 9,500 स्कूल आज भी बिजली से वंचित हैं और 1,700 से अधिक स्कूलों में शौचालय नहीं हैं ङ्क क्या इसी डबल इंजन सरकार के वादे थे? करोड़ों की स्कूल बिल्डिंग में ताले लटक रहे हैं, और शिक्षकों की तनख्वाहें बच्चों की गैरमौजूदगी में दी जा रही हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं, बच्चों के भविष्य की हत्या है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीरिया स्कूल जहाँ से देश के पूर्व राष्टपति शंकरदयाल शर्मा जी पढ़े आज वहां छत से प्लास्टर गिरता है और पूरा फ्लोर प्रवेश > वर्जित है। चौकसे ने शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के गृह जिले नरसिंहपुर के स्कूलों में 8 साल से छात्र नहीं, लेकिन शिक्षक लाखों वेतन ले रहे हैं, इसी प्रकार रायसेन के चांदबड़ गांव में एक करोड़ की लागत से बना स्कूल भवन 8 साल से बंद पड़ा है। उन्होंने सरकार से शिक्षा बजट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं सभी स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं तुरंत मुहैया करवाई जाने की मांग की।

प्रमुख तथ्य

- 12,200 स्कूलों में केवल 1 शिक्षक
- 9,500 स्कूलों में बिजली नहीं
- 1,700+ स्कूलों में शौचालय नहीं
- 1,022 स्कूल पूरी तरह जर्जर
- सांदीपनि स्कूल जैसी झूठी ब्रांडिंग, बच्चों को टीन की छत के नीचे टपकते पानी में पढ़ने के लिए मजबूर
- करोड़ों का बजट, फिर भी अधूरे क्लासरूम और खाली भवन

15 करोड़ 61 लाख लागत के विस्तारित अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र का हुआ भूमि-पूजन

मध्यप्रदेश को औद्योगिक और रोजगार संपन्न राज्य बनाएंगे : सीएम यादव

अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में शीघ्र प्रारंभ होगी पुलिस चौकी, महिला अधिकारी भी होंगी पदस्थ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे उद्योग और कारखाने मंदिरों की तरह हैं, जो लोगों के कष्ट मिटाते हैं। मध्यप्रदेश में उद्योगों का निरंतर जाल फैलाया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को पलायन की आवश्यकता नहीं है, नए उद्योग शुरू होने से प्रदश में तेजी से समृद्धि आएगी। युवाओं को रोजगारपरक उद्योगों में प्रोत्साहन देते हुए 5 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। मध्यप्रदेश को औद्योगिक और रोजगार संपन्न राज्य बनाएंगे और मध्यप्रदेश देश का नंबर एक राज्य होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को भोपाल के निकट अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 416 करोड़ रूपये निवेश वाली 6 नवीन औद्योगिक इकाईयों के भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अचारपुरा विशेष औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र एक्सटेंशन फेज-3 (ग्राम हज्जामपुर) का शिलान्यास भी किया, जो 31.21 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में आज हर पीढ़ी के उद्यमी हैं। जहां गोकलदास एक्सपोर्टस प्रा.लि. के श्री प्रभात सिंह उपस्थित हैं वहीं सिनाई हेल्थकेयर के युवा श्री आदित्य शर्मा और एसेड्स प्राइवेट लिमिडेट के श्री रौनक चौधरी की उपस्थिति प्रसन्नता प्रदान कर रही है। अचारपुरा की तस्वीर बदल गई है। सावन का समय है और यहां उद्योगों की वर्षा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सहित देशभर में उद्योग-व्यापार का वातावरण बना है। मध्यप्रदेश में उद्योग प्रारंभ करने के लिए छोटे-बड़े उम्र की कोई सीमा नहीं है और सरकार के द्वार सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि खुशी का विषय है कि अचारपुरा की फैक्ट्रियों में ऐसी जैकेट बनाई जा रही हैं जो अमेरिका और अन्य देशों में निर्यात होती हैं। मध्यप्रदेश की

6 नई औद्योगिक ईकाइयों का किया भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नए उद्योगों के भूमि-पूजन के साथ-साथ युवा उद्यमियों को भूमि-आवंटन के आशय पत्र भी बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां 6 नई औद्योगिक इकाईयों ऐसेड्स प्राइवेट लिमिटेड, सिनाई हेल्थ केयर, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इंडो एकॉर्ड अपरल्स, थिंक गैस एवं समर्थ अग्रीटेक का रिमोट दबाकर भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर अचारपुरा में पुलिस चौकी काम करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित आईजी (पुलिस) को इस चौकी पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिये।

प्रतिभाएं इन उत्पादों को तैयार कर विश्व में पहुंचा रही हैं। चीन जैसा देश हमारे कॉटन को बेच रहा है। मध्यप्रदेश की कपास की गुणवत्ता विश्व विख्यात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेहनत के मंदिर हमारे कारखाने इस बात के प्रतीक हैं कि वे सभी की तकलीफें दूर करते हैं। उद्योगपतियों की पूंजी और युवाओं का परिश्रम मिलकर अच्छा परिणाम देता है। राज्य सरकार ने देश के अलग-अलग शहरों में उद्योगों की स्थापना के लिए रोड शो आयोजित कर निवेशकों को आकर्षित किया है। राज्य सरकार भारत ही नहीं यूके, दुबई, स्पेन, जर्मनी, जापान सहित अनेक देशों से निवेश लेकर आई हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का नंबर दुनिया में वर्ष 2014 में 15वें स्थान पर था, अब भारत तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्र में संपन्नता लाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में 20 वर्ष पूर्व प्रति व्यक्ति आय 11 हजार रुपए थी, जो अब 1 लाख 52 हजार रुपए हो गई है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर है जिसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करेंगे। प्रदेश की सभी पात्र लाड़ली बहनों को दीपावली के बाद 1500 रुपए की राशि हर माह दी जाएगी। सावन का महीना है, बहनों को शगुन की राशि भी देंगे। लाड़ली बहनों की राशि साल दर साल बढ़ाएंगे और इसे वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाएंगे।

भारतीय नायकों के गौरवशाली इतिहास से युवाओं को परिचित कराने का नाटक सशक्त माध्यमः मुख्यमंत्री

- **6 दिवसीय हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का किया शुभारंभ**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वास्तव में नाटक कला अनूठी है। नाटकों के माध्यम से भारतीय इतिहास के गौरवशाली व्यक्तित्वों की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने संस्कृति विभाग की संस्था मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के सहयोग से रवीन्द्र भवन में आयोजित छह दिवसीय हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व राज्यसभा

सदस्य श्री रघुनंदन शर्मा, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला, राष्टीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री चितरंजन त्रिपाठी, फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य सुश्री वाणी त्रिपाठी और अन्य अतिथि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह संयोग है कि वे हरिहर की नगरी से आते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की चौदह विद्याओं और चौसठ कलाओं में नाट्य शास्त्र के सभी आयाम शामिल हैं। उज्जैन ऐसी नगरी है, जहां भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा हुई साथ ही महाकाल की नगरी होने का आशीर्वाद भी इसे मिला है। उज्जैन में श्रावण माह, कार्तिक माह और अन्य अवसरों पर होने वाले आयोजन अनूठे होते हैं। हमारे इतिहास में जहां राष्ट्र के दुर्बल होने के निराशाजनक उदाहरण देखने को मिलते हैं, वहीं हमारे समर्थ होने के भी प्रमाण मिलते हैं। विदेशी आक्रांताओं ने आराध्य स्थलों को नष्ट करने और प्रतिमाएं अन्य देशों में ले जाने का कृत्य किया, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे पराक्रमी और राष्ट्रप्रेमी शासकों ने उन प्रतीकों को पुनः स्वदेश लाने का कार्य भी किया।

नाटक कला अनूठी है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं विद्यालयीन और महाविद्यालयीन स्तर से नाटकों के मंचन से जुड़े रहे हैं। उन्हें अनेक वर्ष पूर्व महानाट्य जाणताराजा देखने का सौभाग्य मिला, जो शिवाजी महाराज के साहसिक जीवन पर केन्द्रित था। बाद में इस तर्ज पर सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को मंच पर लाने में सफलता मिली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों का उल्लेख करते हुए बताया कि शिवाजी महाराज की तरह सम्राट विक्रमादित्य सुशासन और शौर्य के प्रतीक थे। उनके राज्य का काफी विस्तार हुआ। उन्होंने अपने भूभाग के समस्त नागरिकों का ऋण समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया और विक्रम संवत् के प्रर्वतन की दिशा में आगे बढ़े।

यादव ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के संकल्प पत्र पर किए हस्ताक्षर

समाज को नशा और अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रदेश पुलिस चला रही है जागरुकता अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नशे से दूरी है जरूरी अभियान केवल अभियान नहीं, मादक पदार्थों की लत से युवाओं को बचाने की दिशा में समाज और पुलिस की सहभागिता का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित वृहद जन-जागरूकता अभियान नशे से दूरी-है जरूरी÷ के अंतर्गत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यह अभियान 15 से 30 जुलाई 2025 तक प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस

मुख्यालय के नारकोटिक्स विंग द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य किशोरों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, उन्हें इस लत से दूर रखना और जो लोग पहले से नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें उचित परामर्श और सहयोग प्रदान कर पुनर्वास की दिशा में मार्गदर्शन देना है।

पुलिस के नशा मुक्ति अभियान से जुड़ीं स्वयंसेवी संस्थाएं

नशा मुक्ति अभियान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारी, नगर एवं ग्राम रक्षा समितियां और कम्युनिटी पुलिसिंग के सभी विंग साथ मिलकर स्कूल, कॉलेज के युवाओं और आमजनों को नशे से दूरी बनाने के लिए जागरुक करेंगी। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रदेश स्तरीय महाअभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि जनता में विशेषकर युवाओं में जागृति आए कि नशा किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म कर प्रगति को बाधित कर रहा है। पुलिस का यह कार्य जन-जागरुकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुदाय को कानून, असुरक्षा, गलत नीतियों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, ताकि प्रदेशवासी नशा और अपराध मुक्त वातावरण में एक बेहतर जीवन जी सकें।

मुख्य अभियंताओं के 7 दलों ने 35 निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

छह ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट करने के निर्देश पाँच अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

भोपाल। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार के लिये लोक निर्माण विभाग ने माह दो बार विभाग के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में 23 जुलाई को नर्मदापुरम, सिवनी, ग्वालियर, खरगोन, सीधी, उज्जैन और सागर जिलों में मुख्य अभियंताओं के सात दलों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 35 कार्यों को रैंडम आधार पर चयनित कर निरीक्षण किया गया। इनमें 21 कार्य लोक निर्माण विभाग (सड़क/पुल), 6 कार्य प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (भवन), 7 कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम और 1 कार्य मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के सम्मिलित थे।

निरीक्षण दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा प्रबंध संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम भरत यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इस बैठक में तकनीकी सलाहकार श्री आर.के. मेहरा, प्रमुख अभियंता श्री केपीएस राणा, श्री पी.सी. वर्मा, श्री आनंद प्रकाश राणे, श्री बीपी बौरासी सहित समस्त संबंधित अधिकारी एवं निरीक्षणकर्ता उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन में कई कार्यों में गंभीर अनियमितताएँ सामने आई। सिवनी जिले में चिरचिरा से कोठीघाट तक 6.28 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य मापदण्डानुसार नहीं पाया गया, जिस पर ठेकेदार मेसर्स जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर को ब्लेक लिस्ट करने और उपयंत्री गौरव डेहरिया के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई। सीधी जिले में थोंगा-मैट टोला से जमुआ मार्ग निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता दोष पाए गए, जिसके चलते ठेकेदार मेसर्स ओराट्रिक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रा.लि. को ब्लेक लिस्ट करने एवं अनुविभागीय अधिकारी स्तुति गौतम, उपयंत्री प्रभात श्रीवास्तव तथा कंसल्टेंट के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

ग्वालियर जिले में मसूदपुर से एटमा वाया दौलतपुर मार्ग का निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर ठेकेदार मेसर्स पीताम्बरा आईडियल कंस्ट्रक्शन को ब?लेक लिस्ट करने के निर्देश दिये गये। सीधी जिले में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम का बेहरी से हनुमना मार्ग असंतोषजनक स्थिति में पाया गया, जिस पर ठेकेदार मेसर्स जी.व्ही.आर. टोलवेज़ प्रा.लि. के विरुद्ध कार्यवाही करने और सुधार कार्य ठेकेदार की रिस्क एंड कॉस्ट पर कराने के निर्देश दिये गये। सागर जिले में पाली-पीरघाट-खिमलासा-कंजिया मार्ग की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई, जिस पर ठेकेदार केसीसी बिल्डकोन प्रा.लि. को ब्लेक लिस्ट करने तथा कंसल्टेंट के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सुधार कार्य ठेकेदार की रिस्क एंड कॉस्ट पर कराने के निर्देश दिये गये।

खरगोन जिले में एमएस बोरवाल नवीन हाईस्कूल शाला भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता में दोष पाए जाने पर ठेकेदार मेसर्स स्नेहा कंस्ट्रक्शन को ब्लेक लिस्ट करने एवं उपयंत्री विजेन्द्र भंवर और अनुविभागीय अधिकारी पवन डाबर को कारण बताओ नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई। इसके अलावा अन्य 20 कार्यों में आंशिक सुधार के निर्देश दिए गए।

पेसा कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अमरकंटक में स्थापित होगा उत्कृष्टता केंद्र

भोपाल। भोपाल स्थित वाल्मी परिसर में गुरूवार को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन तथा इंदिरा गांधी राष्टीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू), अमरकंटक के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यम्रम में पेसा कंपेडियम का विमोचन तथा एमओयू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यक्रम में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज, मध्यप्रदेश शासन की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, इंदिरा गांधी राष्टीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ब्योमकेश त्रिपाठी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पेसा पर आधारित एक संक्षिप्त वीडियो फिल्म प्रदर्शित की गई। पेसा के अंतर्गत बेहतरीन कार्यों की कंपेडियम÷ का विमोचन किया गया। इस अवसर पर ÷पेसा को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं संस्थागत सहयोग÷ विषय पर एक विशेषज्ञ पैनल चर्चा भी हुई।

मौसम बिसेन सदस्य नियुक्त, आयोग में पहले से कार्यरत हैं दो सदस्य

डॉ. कुसमरिया ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष पद का किया कार्यभार ग्रहण

भोपाल। मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने श्यामला हिल्स स्थित आयोग कार्यालय में औपचारिक रूप से कार्य भार ग्रहण किया। डॉ. कुसमरिया ने कहा कि आयोग प्रदेश में भ्रमण कर पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति तथा समस्याओं का अध्ययन करेगा और उनके समाधान के लिये सुझाव प्रस्तुत करेगा। साथ ही पिछड़े वर्ग को उनके आरक्षण संबंधी अधिकार दिलाने के लिये भी कार्य किया जाएगा।

डॉ. कुसमरिया ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से कृषि में एम.एससी. एवं कृषि अर्थशास्त्र में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की है। वे पूर्व में दमोह एवं खजुराहो संसदीय क्षेत्रों से सांसद और विधायक रह चुके हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश शासन में कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में वे मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के

अध्यक्ष भी हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष पद संभालने के उपरांत दोनों आयोगों के मध्य बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया जा सकेगा।

आयोग में श्रीमती मौसम बिसेन को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोग में पूर्व से दो सदस्य कार्यरत हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे, नगर पालिका अध्यक्ष बालाघाट श्रीमती भारती ठाकुर, श्री सत्यनारायण अग्रवाल, श्री कन्हैया चौहान, श्री संजय मिश्रा, श्री गोलू ठाकुर, श्री सागर बिसेन सहित प्रदेश भर के कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

किसान परंपरागत खेती के साथ तकनीक का भी उपयोग करें: उद्यानिकी मंत्री कुशवाह

भोपाल। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि किसान परंपरागत खेती पर ही निर्भर न रहें बल्कि नवीन तकनीकी के साथ उद्यानिकी फसलों को लेने की ओर बढ़ें। उन्होंने यह बात उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनांतर्गत ग्वालियर जिले में उद्यानिकी फसलों को बढावा देने के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ अवसर पर कही। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति श्री अरविंद कुमार शुक्ला, कृषि वैज्ञानिक और जिले के प्रगतिशील किसान बडी संख्या में उपस्थित रहे।

मंत्री कुशवाह ने कहा कि गांव में अधिक से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट एवं छोटे छोटे उद्योग लगायें जिससे किसान खुद की फसल का अच्छा दाम प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार नई योजना ला रही है

जिसमें जो भी किसान एक बगिया माँ के नाम लगाने पर सरकार 3 लाख रुपये तक अनुदान प्रदान करेगी। उन्होने कहा कि किसानों की मेहनत के कारण लगातार खाद्यान उत्पादन में मध्यप्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के किसान फसलों की सिंचाई के लिए काफी परेशान रहते थे, जबसे नदी जोडो अभियान चला है और नये डेम बने है, तब से सिंचाई का रकवा काफी बडा है, जिस कारण फसल उत्पादन भी बडा है।

उद्यानिकी मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि हमें जैविक खेती को बढावा देना होगा, किसानों को अपनी फसलों में कम से कम कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों का अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हो इसके लिए सरकार प्रयासरत है। किसानों को आईएसआई मार्क की ही मशीनरी एवं अन्य सामान उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

कार्यशाला में कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति श्री अरविंद कुमार शुक्ला ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से किसान अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। परंपरागत खेती के साथ-साथ उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर किसान कार्य करे तो उनकी आय दोगुना हो सकती है। कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नए-नए अनुसंधानों के बारे में भी किसानों को जानकारी प्राप्त कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा भी किसानों को उद्यानिकी फसलों के संबंध में तकनीकी जानकारी दी गई।

संपादकीय

अब न्यायिक पीठ के फैसले या उसकी प्रतिक्रिया पर नजर

चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के संदर्भ में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड 'वैध दस्तावेज' नहीं हैं, लिहाजा उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। बिहार में पुनरीक्षण का करीब 96 फीसदी काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत के आग्रह को नकार दिया है, लिहाजा अब न्यायिक पीठ का फैसला अथवा उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, यह 28 जुलाई को सुनवाई के दौरान सामने आ सकता है। सर्वोच्च अदालत या तो न्यायिक आदेश देती है अथवा निर्देश देती है, जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। अब अदालत और आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी परस्पर मर्यादाएं हैं, लिहाजा अहम सवाल है कि क्या आयोग बनाम अदालत की स्थिति बन गई है? क्या शीर्ष अदालत भविष्य के मतदाता-सूची पुनरीक्षण के मद्देनजर आधार, वोटर और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने को चुनाव आयोग को बाध्य कर सकती है? चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया है कि मतदाता की नागरिकता का पता लगाना भी उसका संवैधानिक अधिकार है। बेशक यह मुद्दा भी सर्वोच्च अदालत के सामने उठेगा, क्योंकि न्यायिक पीठ कहती रही है कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। वह गृह मंत्रालय का संवैधानिक जनादेश है। लिहाजा मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में, बिहार में ही, जिन 52 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटने की संभावना आयोग ने जताई है, क्या उनकी नागरिकता भी सवालिया हो जाएगी? यह तय करने वाला चुनाव आयोग कौन होता है? आयोग ने अभी तक जो डाटा इकट्ठा किया है, उसके मद्देनजर आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में रेखांकित किया है कि बिहार की मतदाता सूचियों में करीब 18 लाख मृतकों के नाम दर्ज हैं, 26 लाख ऐसे नाम हैं, जो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और वहां के मतदाता हैं, 7 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दो-दो स्थानों पर हैं। इस तरह 52 लाख से अधिक नाम मतदाता-सूची से काटे जा सकते हैं। बेशक ऐसे मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान अपील कर सकते हैं। क्या नागरिकता से जुड़े ऐसे मामले सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच सकते हैं? बिहार में चुनाव आयोग के पुनरीक्षण-अभियान का जबरदस्त राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि विधानसभा में मेज-कुर्सियां उछाली गईं। मार्शल (सुरक्षाकर्मी) और विपक्षी विधायक आपस में भिड़ गए, धक्कामुक्की, हाथापाई तक की नौबत आ गई। संसद परिसर में भी विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर संसद भवन के 'मकर द्वार' पर विरोध-प्रदर्शन किया। संसद के भीतर विपक्षी सांसद अध्यक्ष के आसन तक 'वेल' में लामबंद हुए। नारेबाजी का शोर इतना था कि सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। दोनों सदनों की कार्यवाही दोनों दिन नहीं चल सकी। बेशक चुनाव आयोग के अभियान से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है अथवा नहीं, अलबत्ता लोकतंत्र लगातार 'लहूलुहान' जरूर हो रहा है। अब सर्वोच्च अदालत को एक निश्चित फैसला सुना कर देश के लोकतंत्र को बचाना है। अब तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है कि आयोग बंगाल में ऐसे 40 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 में चुनाव आयोग को पुनरीक्षण के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। आयोग मतदाता-सूचियों में संशोधन कर सकता है। नाम काटे जा सकते हैं, तो नए मतदाताओं के नाम जोड़े भी जाते हैं। चूंकि आजकल बांग्लादेशी घुसपैठियों, म्यांमार की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों की चर्चा खूब है। सरकारें अवैध घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज रही है। यदि आधार, राशन, वोटर कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज नकली, फर्जी बनाए जा रहे हैं, तो यह देश पर कलंक है। ऐसे कार्डधारकों की छंटनी होनी ही चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ऐसे माहौल में सर्वोच्च अदालत का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि वह ऐसी छंटनी को वैधता प्रदान करे।

ट्रंप को आईना दिखाती, भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड डील

कौशल किशोर चतुर्वेदी

इन दिनों जब पूरी दुनिया के देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारी भरकम ट्रेड टैरिफ लगाने का डर दिखा रहे हैं, तब भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर ट्रंप को आईना दिखाने जैसा है। भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार यानि 24 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की मार्केट पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होने के साथ वार्षिक द्विपक्षीय कारोबार में करीब 34 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी। वहीं ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने बुधवार यानि 23 जुलाई 2025 को एक समझौते की घोषणा की जिसके तहत जापान से अमेरिकी आयात पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा, जो अमेरिका द्वारा पहले प्रस्तावित 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क से कम है। यानी अमेरिका ने ज्यादा टैरिफ लगाने का डर दिखाकर उसमें जो कमी की है, बस वही संतोष करने के लिए काफी है। पर अब ब्रिटेन-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने अमेरिका की आंखें खोल दी होंगी। और यह भी जता दिया होगा कि भावी वैश्विक व्यापार की दिशा एफटीए ही है। और एफटीए यह भी बता रहा है कि व्यापार संबंधों में भी भारत दुनिया को राह दिखा रहा है और आगे वैश्विक संबंधों में भी विश्व गुरु बन पूरी दुनिया को राह दिखाने में सक्षम है।

भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर व्यापार के नए युग का संदेश दे दिया है। इससे दोनों देशों की मार्केट पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होने के साथ वार्षिक द्विपक्षीय कारोबार में करीब 34 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर की मौजूदगी में एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकारियों ने कहा कि एफटीए के लागू होने पर 99त्न भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में शुल्क नहीं लगेगा।दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनियों के लिए व्हिस्की, कारों एवं अन्य प्रोडक्ट भारत में निर्यात करना आसान हो जाएगा। इस तरह समग्र द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी। हालांकि इसकी तैयारी कई सालों से चल रही थी। दोनों देशों के बीच 3 साल की बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा सका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफटीए के संदर्भ में कहा कि आज का दिन भारत-ब्रिटेन संबंधों में ऐतिहासिक है। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने एफटीए के संदर्भ में कहा कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद यह ब्रिटेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करके हम एक बहुत ही प्रभावशाली संदेश दे रहे हैं कि ब्रिटेन व्यापार के लिए खुला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता, यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार विचार शेयर कर रहे हैं।

दूसरी तरफ अमेरिका ने जापान समेत कई एशियाई देशों के साथ ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने एक समझौते की घोषणा की जिसके तहत जापान से अमेरिकी आयात पर 15त्न शुल्क लगाया जाएगा, जो अमेरिका द्वारा पहले प्रस्तावित 25त्न से कम है।

वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि चीन के साथ वार्ता को अधिक समय देने को 12 अगस्त की समयसीमा को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत के साथ बातचीत की स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, इसकी प्रगति देश के अत्यधिक संरक्षित कृषि क्षेत्र पर निर्भर प्रतीत होती है। देश पर 26 प्रतिशत शुल्क का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, कई खबरें आई हैं कि 1 अगस्त से पहले भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम ट्रेड डील हो सकती है। इसके बाद अक्टूबर में फाइनल ट्रेड डील होगी। फिलिपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि उनके देश से आयातित उत्पादों पर 19 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। यह पहले प्रस्तावित 20 प्रतिशत शुल्क से केवल एक प्रतिशत कम है। इंडोनेशिया को भी 19 प्रतिशत शुल्क सामना करना पड़ेगा, जो कि पहले प्रस्तावित 32 प्रतिशत की दर से कम है। इससे पहले, ट्रंप ने घोषणा की थी कि वियतनाम के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा, जो चीन से आने वाले सामान पर दोगुना होगा। हालांकि, इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

तो भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए होने के बाद यह साफ हो गया है कि ट्रेड टैरिफ के मामले में पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। और व्यापार यानि आर्थिक संबंधों के साथ-साथ सामरिक, सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध भी फलेंगे फूलेंगे। और भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील के साथ दुनिया का यह बदलता परिदृश्य अमेरिका और ट्रंप को आईना दिखाता रहेगाज।

संसद का संकटकाल: महाभियोग की राजनीति, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और सत्ता-विपक्ष की अदृश्य जंग

राजेश जयंत

भारतीय संसदीय लोकतंत्र अपने सबसे विचित्र और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। बीते सप्ताह संसद भवन में जो राजनीतिक विस्फोट हुआ, उसने न केवल संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा पर प्रश्नचिह्न लगाया, बल्कि सत्तारूढ़ दल, विपक्ष, न्यायपालिका और सोशल मीडिया- सभी को असहज कर दिया। जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, राज्यसभा के मंच पर फैसला पलट, और अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखढ़ का इस्तीफाज्यह सब बेहद गहरी पटकथा का हिस्सा था, जिसमें सच्चाई, रणनीति और विश्वास तीनों की असली परीक्षा थी।

सरकार की नियंत्रण नीति और विपक्ष की तगड़ी चूकः केंद्र सरकार शुरू से चाहती थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लोकसभा में लाया जाए, ताकि पूरा नियंत्रण और नैतिक एजेंडा उसके पास रहे। पर राजनीति की बिसात पर अचानक एक चाल उलट गई- राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखढ़ ने विपक्ष द्वारा प्रस्तुत 63 सांसदों के हस्ताक्षरयुक्त महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर डाला। राजनीतिक तकरार का नाटकीय मोड़ः यह अप्रत्याशित कदम विपक्ष की रणनीतिक जीत थी। राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट बढ़ गई—क्या जस्टिस वर्मा

को बचाने की कोई गुप्त डील हुई आश्चर्य इस बात का भी रहा कि न्यायपालिका की स्वच्छता पर बहस छेड़ने वाले धनख अब विपक्षी स्क्रिप्ट का अनचाहा नायक क्यों बन गए सोशल मीडिया पर जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए और संसद की घटाएं ट्विटर-फेसबुक तक जा पहुंचीं। जस्टिस शेखर यादवः इसी बीच प्रयागराज हाईकोर्ट के जज शेखर यादव, जिन्होंने वीएचपी मंच से विवादास्पद बयान दिया था, उनके खिलाफ भी विपक्ष ने महाभियोग की कवायद तेज कर दी। यहां सत्ता पक्ष चाहता था कि यादव बचें और विरोधी चाहते थे कि वे हटें, पर धनखड़ का पक्ष झुकते ही सियासी फलक झनझना उठा।

आंतरिक संकट, डैमेज कंट्रोल और इस्तीफाः सत्ता पक्ष को लगने लगा कि धनखड़ विपक्ष की लाइन ले सकते हैं। तुरंत एनडीए सांसदों से सादे काग? पर साइन कराए गए; संकट गहराते ही 'डैमेज कंट्रोल' शुरू हुआ। अर्द्धरात्रि के समीप धनख? ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंप दिया। विपक्ष ने उन्हें ÷लोकतंत्र का प्रहरी÷ जताया तो प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत शिथिल दिखी। सत्ता पक्ष को यह राहत वाला घटनाक्रम लगा। कार्यालय स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं । विपक्ष इन कार्रवाइयों को सत्ता की बौखलाहट व बदले की कार्रवाई बता रहा है, वहीं सरकार इसे ÷सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया कहकर कम कर आंक रही है।

सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति ऑफिस पर लगे ताले की फोटो और आवास की निगरानी की खबरें वायरल हैं— और जैसे हैशटैग तेजी से चल रहे हैं।

जस्टिस वर्मा और शेखर यादव के महाभियोग मामले ने मात्र एक संवैधानिक प्रक्रिया या दलगत राजनीति नहीं, बल्की भारतीय लोकतंत्र के न्यूक्लियस को चुनौती दी है। संसद, न्यायपालिका, विपक्ष- तीनों की नीयत, सीमा और रणनीति कटघरे में हैं। सोशल मीडिया ने इस समूचे प्रसंग को 'पब्लिक कोर्ट' में ला के खड़ा कर दिया है, लिहाजा अब हर निर्णय केवल संविधान की किताब तक सीमित नहीं, बल्कि जनता की भावना, भरोसा और सवालों के मध्य से होकर गुजरेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक ही संदेश दिया- आज संसद का सीधा युद्ध संसद भवन से निकल कर हर हाथ के मोबाइल, हर आम आदमी की राय और 'औनलाइन जनमत' तक पहुँच गया है। क्या लोकतंत्र अब और ज्यादा पारदर्शिता की ओर बढ़ेगा या उलझनों के बियाबान में खो जाएगा, इसका उत्तर अब नेताओं या जजों के पास नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और सोशल मीडिया के तापमान में छुपा है।

शहरी सामूहिकता

राकेश दुबे

शहरी अर्थव्यवस्थाओं में सामूहिकता बहुत मायने रखती है। ?जब कंपनियां, कर्मचारी और योजनाकार सब एक जगह होते हैं, तो वे साझा बुनियादी ढांचे, संयुक्त श्रम और नवाचार का लाभ उठाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल से लेकर एडवर्ड ग्लेसर तक तमाम अर्थशास्त्रियों ने एक ही जगह उपलब्ध सभी सुविधाओं वाले ऐसे केंद्रों की सराहना करते हुए इन्हें उत्पादकता एवं विकास का इंजन बताया है। पिछले कुछ समय से भारत के कई बड़े शहरों ने अपने यहां ऐसी ही एकीकृत सुविधाओं, रोजगार ढांचे को विकसित करने पर जोर दिया है।

बेंगलूरु ने तकनीकी कंपनियों और इंजीनियरों को आकर्षित किया है, तो मुंबई ने अपने कुछ वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही वित्त, मीडिया और महत्त्वाकांक्षी लोगों को केंद्रित किया है। सैद्धांतिक रूप में एकीकृत शहरी व्यवस्था से उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए थी और शायद कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी। लेकिन अब जबकि बेंगलूरु अत्यधिक यातायात के दबाव से जूझ रहा है, मुंबई में आवासीय संकट है और दिल्ली का दम धुएं (प्रदूषण) से घुट रहा है, तो सवाल उठता है कि विकास का यह रास्ता कितना कारगर है? देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शहरों का योगदान 60 फीसदी से अधिक है और वर्ष 2030 तक इसके बढ़कर 70 फीसदी तक हो जाने का अनुमान है। दिल्ली, बेंगलूरु और मुंबई जैसे महानगरों में लगातार पूंजी निवेश हो रहा है और श्रमबल खिंचा चला रहा है। सरकार भी स्मार्ट सिटी, स्वच्छ ऊर्जा और हाई-स्पीड रेल जैसी सुविधाओं के साथ इन शहरों की गतिशीलता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

इनसे शहरी जीवन आसान जरूर लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि बेंगलूरु की दिनचर्या हर रोज 190 किलोमीटर के दायरे में घूमती है। कर्नाटक में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक चेंज के अनुमान के मुताबिक यातायात जाम के कारण बेंगलूरु को अपने उत्पादक घंटों में कमी आने की वजह से 1,170 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। मेट्रो अभी पूरे शहर और इसके आसपास उभरते उपनगरों को कवर नहीं कर पाई है। कागजों में देश के रहने लायक सबसे अच्छे शहरों में शुमार पुणे ने पिछले एक दशक में अपनी हरियाली का एक तिहाई हिस्सा खो दिया है।

असल बात यह है कि समूहीकरण केवल शहरों में अधिक से अधिक लोगों के बसने का नाम नहीं है। यह जीवन की गुणवत्ता के बारे में है। शहरी उत्पादकता तब बढ़ती है जब लोग आपस में सहयोग करते हैं। एक साथ घूमते-फिरते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं। लेकिन यदि शहर में काम के सिलसिले में हर रोज दो घंटे सफर करना पड़े, आवास पर ही आधी कमाई खर्च हो जाए और लू चलने से लोगों की रोज की कमाई पर ही संकट आ जाए तो सुविधाओं का केंद्रीकरण बेमानी हो जाता है।

एशिया के अन्य शहरों में सिंगापुर का ही उदाहरण लें, जहां एकीकृत भू-उपयोग और परिवहन योजनाएं इस तरह डिजाइन की गई हैं कि लोगों की उत्पादकता बढ़ गई है और वे यहां रहने के लिए प्रेरित होते हैं। वहां के मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (रेल प्रणाली) से प्रतिदिन 30 लाख से अधिक लोग आवाजाही करते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि वहां बहुत पहले ही भीड़भाड़ से निपटने के लिए ठोस योजनाएं तैयार कर ली गई थीं। इसी तरह वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर ने भी अपनी बढ़ती आबादी के मुद्दों से निपटने के बेहतर इंतजाम किए हैं। यहां केंद्रित औद्योगिक क्षेत्र और रणनीतिक ढांचागत निवेश के कारण श्रम उत्पादकता हनोई शहर की तुलना में लगभग दोगुनी है। आज अधिकांश भारतीय शहर पलायन के दौर से गुजर रहे हैं। यह इसलिए नहीं हो रहा कि वे सफलताओं की सीमाओं को पार कर चुके हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अभी तक अपने निवासियों एवं उद्योगों की बुनियादी जरूरतों से जुड़े वादे तक पूरे नहीं किए हैं। आबादी, नौकरियों और सेवाओं को एक जगह लाने से उत्पादकता एवं नवाचार को बढ़ाने तथा आर्थिक मौकों को भुनाने की उम्मीद थी लेकिन समन्वित रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। नतीजतन कई शहरों की आबादी तो बढ़ी है, लेकिन उनकी गतिशीलता और उत्पादकता नहीं बढ़ी है। तरक्की के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत होती है। भारतीय शहरों को अपने पुनर्संयोजन की प्रक्रिया अपनानी होगी। दीर्घावधि विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें नए सिरे से गुणवत्ता, लचीलेपन और समानता पर केंद्रित एवं बेहद सुविचारित योजनाएं लागू करनी होंगी।

विश्व डूबने से बचाव दिवस

तैराकी हृदय स्वास्थ्य में सुधार, मांसपेशियों को मजबूत बनाने, वजन और तनाव कम करने में मदद करती

महेश अग्रवाल
योग गुरु

आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र स्वर्ण जयंती पार्क कोलार रोड़ भोपाल के योग गुरु महेश अग्रवाल ने बताया कि 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है । इस दिन का उद्देश्य डूबने के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ड्राउनिंग के मुद्दों को समझाने के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के महत्व को बढाया है। विश्व डूबने से बचाव दिवस 2025 की थीम है - अपनी कहानी एक जीवन बचा सकती है । यह थीम डूबने के जोखिमों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने में व्यक्तिगत कहानियों की भूमिका पर जोर देती है। यह उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जिन्होंने डूबने की घटनाओं से बचे हैं या पानी से संबंधित त्रासदियों का अनुभव किया है, अपनी कहानियां साझा करें, दूसरों को शिक्षित करें, कार्रवाई के लिए प्रेरित करें, और पानी से संबंधित आघात या डर से जूझ रहे लोगों का समर्थन करें।

योग गुरु अग्रवाल ने इस अवसर पर जीवन में तैराकी का क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी दी। तरण या तैराकी एक जलक्रीड़ा है। इसके अन्तर्गत अपने हाथ-पैर की सहायता से जल में गति करना होता है जो किसी कृत्रिम साधन के बिना किया जाता है। तैराकी मनोरंजन भी है और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकार भी। तैरना मनुष्य के लिये बहुत आवश्यक है। तैरने से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं जैसे की हम अपने या दूसरों को डूबने से बचा सकते हैं। हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। अच्छी तरह तैरने से आत्मविश्वास बढ़ता है।

तैराकी एक उत्कृष्ट व्यायाम है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है। यह हृदय स्वास्थ्य में सुधार, मांसपेशियों को मजबूत बनाने, वजन कम करने और तनाव कम करने में मदद करता है।

तैराकी एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में खेला जाता है। तैराकी में पानी में चलने के लिए पूरे शरीर की गतिविधि शामिल होती है। तैराकी छोटे तालाबों, नदियों, तालाबों और कुओं में की जा सकती है।

तैराकी पूरे शरीर के व्यायाम के लिए जानी जाती है, और यह व्यायाम का एक कम प्रभाव वाला रूप है जो जोड़ों के लिए आसान है। तैराकी ओलंपिक खेलों में से एक है।

तैराकी के फायदे – तैराकी से आपको ढेर सारी कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है और जोड़ों पर भी आराम पड़ता है। यह आपको वजन बनाए रखने, मांसपेशियों की ताकत हासिल करने और सहनशक्ति में सुधार करने में मदद करता है। यह सुरक्षित और स्वस्थ खेलों/व्यायामों में से एक है जिसे उम्र बढ़ने के साथ भी किया जा सकता है।

तैराकी के कुछ लाभ सहनशक्ति बनाता है तैराकी को एक एरोबिक व्यायाम माना जाता है, क्योंकि तैराकी के दौरान आप लगातार सांस लेते हैं। तैराकी सहनशक्ति बनाने के लिए, आपको उत्कृष्ट एरोबिक क्षमताओं की आवश्यकता है। सहनशक्ति समय के साथ बार-बार सबमैक्सिमल संकुचन करने की मांसपेशियों की क्षमता है । यह आपके शरीर की समग्र सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। तैराकी उन व्यायामों में से एक है जो दौड़ने और वजन प्रशिक्षण से अधिक प्रभावी है।

खेल की कम प्रभाव वाली प्रकृति के कारण ही एथलीट तैराकी की ओर रुख करते हैं। यह आपके जोड़ों पर बहुत कठोर नहीं है, लेकिन जिम में आपके द्वारा किए जाने वाले वर्कआउट जितना प्रभावी है और सहनशक्ति भी बढ़ाता है।

मांसपेशियों की ताकत तैराकी में, मांसपेशियों की ताकत तैरना महत्वपूर्ण है, यह वह बल है जो आपकी मांसपेशियां पानी में लगा सकती हैं। लागू की गई मांसपेशियों की ताकत आपको पानी में आगे बढ़ने में मदद करती है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करें मधुमेह से पीड़ित लोगों को प्रतिदिन कम से कम एक घंटा शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए और यह तनावपूर्ण हो सकता है अगर लोग अपनी दिनचर्या से चूक जाएं। यह मधुमेह वाले लोगों के लिए एक कार्डियोवैस्कुलर कसरत है और रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है। मधुमेह रोगियों को तैराकी करते समय अपने पैरों और आंखों का ख्याल रखना चाहिए।

चूंकि तैराकी में हाथ और पैर एक साथ चलते हैं, इसलिए मोटर प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होगी। तैराकी जैसी मनोरंजक गतिविधि विकलांग बच्चों की मदद करती है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और अच्छे पारिवारिक संबंध बनाने में भी मदद करता है। तैराकी एक हृदय संबंधी गतिविधि है जो आपकी हृदय गति को बढ़ाती है और आपके शरीर को अधिक ऑक्सीजन का उपभोग करने में मदद करती है। चलना अक्सर हृदय संबंधी फिटनेस के लिए स्वर्णिम मानक है, क्योंकि इसके लिए किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। तुलनात्मक रूप से, तैराकी हृदय संबंधी फिटनेस के लिए भी अच्छी है। तैराकी हृदय और फेफड़ों के लिए सबसे अच्छा काम करती है। तैराकी शरीर को ऑक्सीजन का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करती है। पूरे शरीर में हलचल होती है, जिससे ताकत और लचीलेपन में सुधार होता है।

तैराकी का दूसरा पक्ष यह है कि यह आपको सांस लेने और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग को शांत करने देगा। तनाव-खत्म करने वाली विशेषता इसे सर्वश्रेष्ठ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बनाती है।

दिल फेफड़े स्वस्थ रहते हैं तैराकी से तनाव कम होता है

जलीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर बच्चों के लिए। डूबने से बचाव के लिए पर्यवेक्षण और सावधानी बरतना आवश्यक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जलीय सुरक्षा के लिए ध्यान में रखनी चाहिए - बच्चों की सुरक्षा के लिए सुझाव - माता-पिता या अभिभावक की निगरानी, 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों को हर समय माता-पिता या अभिभावक की पहुँच में रहना चाहिए। सतर्क रहना - माता-पिता या अभिभावक को बच्चों पर लगातार दृश्य संपर्क बनाए रखना चाहिए और विकर्षणों से मुक्त रहना चाहिए। मोबाइल फोन, लंबी बातचीत या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों के प्रयोग से बचना चाहिए।

जलीय सुरक्षा के लिए रणनीतियाँ - जलीय पर्यावरण में जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित जोखिम ऑडिट करना चाहिए। जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय रणनीतियों को क्रियान्वित करना चाहिए। बच्चों और वयस्कों को जल सुरक्षा के महत्व और डूबने से बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए जल सुरक्षा को प्राथमिकता देना इस दिन को मनाने का उद्देश्य जल सुरक्षा को प्राथमिकता देने और डूबने से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना नज़दीक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें- यह नारा जल सुरक्षा के महत्व को दर्शाता है और लोगों को जल सुरक्षा के प्रति जाग रूक करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

तैरना सीखने के लिए योग अभ्यास एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि यह शरीर की लचीलापन, संतुलन और श्वास नियंत्रण में सुधार कर सकता है, जो तैरने के लिए आवश्यक हैं। तैरना सीखने के लिए योग अभ्यास के लाभ -योग अभ्यास शरीर की लचीलापन में सुधार कर सकता है, जो तैरने के लिए आवश्यक है। योग अभ्यास संतुलन में सुधार कर सकता है, जो तैरने के दौरान शरीर की स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। श्वास नियंत्रण - योग अभ्यास श्वास नियंत्रण में सुधार कर सकता है, जो तैरने के दौरान श्वास लेने और छोड़ने में मदद करता है। तैरना सीखने के लिए भुजंगासन एक योग आसन है जो कंधों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जो तैरने के लिए आवश्यक हैं। मकरासन एक योग आसन है जो कंधों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जो तैरने के लिए आवश्यक हैं। शलभासन एक योग आसन है जो पीठ और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जो तैरने के लिए आवश्यक हैं।

तैरना सीखने के लिए योग अभ्यास के सुझाव - योग अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए ताकि शरीर की लचीलापन और संतुलन में सुधार हो सके। योग अभ्यास धीरे-धीरे शुरू करना चाहिए और शरीर की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। श्वास नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए और श्वास लेने और छोड़ने की तकनीक में सुधार करना चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भरत पटेल द्वारा इंडिपेंडेंट प्रेस 11, प्रेस काम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित तथा 226, एमपी नगर जोन-2, भोपाल से प्रकाशित। संपादक — भरत पटेल, प्रबंध सलाहकार — भारती पटेल, संपादकीय सलाहकार — विष्णु कौशिक, सलाहकार संपादक - स्मिता पटेल, स्थानीय संपादक —हाकम सिंह गुर्जर
प्रकाशन से संबंधित समस्त समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त न्यायिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय का रहेगा। रजि. नं. भोपाल डिवी. 48 म. प्र. ई-मेल : dspbpl67@gmail.com, वेबसाईट: dainiksandhyaprakash.in

मंत्री लखन पटेल के क्षेत्र में सामुदायिक भवन में लग रहा स्कूल नहीं है स्कूल का भवन

दैनिक सांध्य प्रकाश, दमोह। जिले के बटियागढ़ विकास खंड के पिपरौधा शासकीय प्राथमिक शाला की क्लासे पहली से पांचवी तक की एक साथ एक ही कमरे मे वो भी सामुदायिक भवन में संचालित हो रही जब यहा पदस्थ शिक्षक से बात की तो उन्होंने बताया की स्कूल का नाम पिपरौधा शासकीय प्राथमिक शाला और पहली से पांचवी तक के बच्चे एक क्लास में एक साथ बैठते हैं और स्कूल में 35 बच्चे दर्ज है दो शिक्षक हैं तीन वर्ष से अधिक हो गए सामुदायिक भवन में लगा रहे हैं शिक्षक ने यह भी बताया कि सामुदायिक भवन में लगाने का कारण स्कूल के भवन की छत नहीं है इसलिए हमें बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से समुदाय भवन में स्कूल लगाना पड़ रहा है शिक्षक ने बताया कि अपने संकुल में और बी.आर.सी में और कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया उसके बाद भी कोई ध्यान नही दे रहा ?

नरसिंहपुर व करेली में स्कूल वाहनों की हुई चेकिंग दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर 7 हजार रुपए का जुर्माना

नरसिंहपुर। नवागत जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा गुरूवार को नरसिंहपुर और करेली में स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान 20 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 3 वाहनों के दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर 7 हजार रुपये का समन शुक्ल अधिरोपित किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूल प्रशासन को समस्त वाहनों के सभी दस्तावेज पूर्ण करने के लिए कहा गया। उन्होंने स्कूल बसों में मेडिकल किट, अग्निशमन यंत्र आदि दुरूस्त रखने की समझाइश दी। उल्लेखनीय है कि गत माह जिला परिवहन अधिकारी रवि बारोनिया ग्वालियर से नरसिंहपुर स्थानांतरित हुए है, उन्होंने बताया कि बच्चों को सुरक्षित स्कूल आने-जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले समस्त वाहन आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही मानक स्तर पर फिजीकल रूप से भी पूर्ण फिट होना चाहिए उनमें सुरक्षा के भी पूर्ण इंतजाम होना आवश्यक है, यह कार्यवाही जिले में निरंतर जारी रहेगी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज आयेंगे आष्टा, अटल सेतु सहित करोड़ों के विकास कार्यो का करेंगे लोकार्पणः भूमिपूजन

आष्टा । मप्र शासन के नगरीय निकाय एवं विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय आज 25 जुलाई शुक्रवार को शाम 4 बजे आष्टा आयेंगे । मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय आज आष्टा नगर की जीवनदायनी पार्वती नदी पर बने लगभग 11 करोड़ की लागत से बने अटल सेतु,79.68 लाख से बने तीन संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण कर इसी के साथ 422.54 लाख से बनने वाले नवीन नगर पालिका कार्यालय भवन,209.07 लाख से कमल तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भूमिपूजन करेंगे । वही 50 लाख से आई 5 नई डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन एवं एक गौभोज वाहन लोकार्पित करेंगे । अटल सेतु पार्वती नदी पुल पर आयोजित लोकार्पण भूमिपूजन कार्यक्रम में मप्र शासन के लोक निर्माण मंत्री राकेशसिंह,प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर, सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी,जिला भाजपा अध्यक्ष नरेश मेवाडा,आष्टा विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर,जिला पंचायत अध्यक्ष रचना सुरेन्द्र मेवाडा,नगर पालिका अध्यक्ष हेमकुंवर रायसिंह मेवाडा,जनपद अध्यक्ष दीक्षा सोनू गुणवान, नपा उपाध्यक्ष सिद्दीका बी भुरू खा अतिथि के रूप में उपस्तिथ रहेंगे । नगर पालिका परिषद ने सभी नागरिको से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है ।

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आग्रह पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

पीडीएस में चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाई, अब 75 :25 के अनुपात में होगा वितरण

भोपाल। प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अब अधिक मात्रा में गेहूं मिलेगा। वर्षों से लंबित इस मांग को प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सतत प्रयासों के चलते आखिरकार केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब पात्र परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न में 75 प्रतिशत गेहूं और 25 प्रतिशत चावल वितरित किया जाएगा। जबकि अभी तक चावल और गेहूं 60 ∶ 40 के अनुपात में वितरित किया जाता था। खाद्यान्न वितरण के इस अनुपात में बदलाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी पर निराकरण नही हो पा रहा था। खाद्य मंत्री बनने के बाद प्रदेश में विभिन्न जिलों के दौरे पर श्री राजपूत से कई बार जनता के माध्यम से यह अनुरोध सामने आया कि इस सिस्टम में बदलाव कर गेहूं की मात्रा ज्यादा करते हुए 75 फीसदी और चावल की 25 फीसदी कर दी जाय। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन एक निर्धारित अनुपात में किया जाता है। मध्यप्रदेश में बहुसंख्यक आबादी चावल की तुलना में गेहूं का अधिक उपयोग करती है, लेकिन पूर्ववर्ती व्यवस्था इसके विपरीत थी। इस व्यावहारिक विसंगति को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इस मुद्दे को प्रभावशाली ढंग से उठाया, और मात्र एक सप्ताह के भीतर केंद्र से सहमति प्राप्त कर ली।

श्री राजपूत ने केंद्रीय मंत्री श्री जोशी को यह भी अवगत कराया कि मध्यप्रदेश में चावल की आवश्यकता कम है, जबकि अधिक मात्रा में मिलने वाला चावल अक्सर बाजार में औने-पौने दामों पर बेचा जाता है या दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। इसके विपरीत, यदि हितग्राहियों को उनकी पसंद और जरूरत के अनुसार गेहूं मिले, तो यह व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सकेगी, क्योंकि मध्यप्रदेश में गेहूं बहुतायत में होता है। इस समस्या के समाधान के लिये मप्र में पात्र हितग्राहियों को दिये जाने वाले खाद्यान्न में गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाना हितकारी होगा। खाद्य मंत्री श्री राजपूत का यह सुझाव केन्द्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को समसामयिक और उपयोगी लगते ही उन्होंने इस पर त्वरित निर्णय कर एक नई राह तय की है।

राजपूत ने माना केंद्रीय मंत्री का आभार, बोले, निर्णय से उपयोगिता और स्वीकार्यता बढ़ेगी

खाद्य सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण और सारगर्भित त्वरित निर्णय पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी का सहृदयता से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न में चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाने के अनुरोध को महज एक हफ्ते के अंदर ही स्वीकार कर उसमें बदलाव के आदेश जारी करना यह बताता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार जनहित के लिए किसी भी निर्णय पर त्वरित अमल करती है। श्री राजपूत ने कहा कि खाद्यान्न उपार्जन से लेकर पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण तक व्यवस्था में लगातार बदलाव के प्रयास होते रहेंगे। केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुविधाओं का विस्तार है ताकि कोई पात्र हितग्राही वंचित न रहे। श्री राजपूत ने कहा कि पीडीएस का मूल उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग को खाद्य सुरक्षा देना है। नए वितरण अनुपात के तहत अब मध्यप्रदेश के हितग्राहियों को अधिक उपयोगी और पसंदीदा अनाज गेहूं, उनकी जरूरत के अनुसार मिलेगा, जिससे योजना की उपयोगिता और स्वीकार्यता दोनों में वृद्धि होगी।

केंद्र का फैसला नीतिगत बदलाव की दिशा में एक मिसाल

राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल जनहितैषी है, बल्कि यह केंद्र राज्य समन्वय का भी सशक्त उदाहरण है। यह दर्शाता है कि यदि मांग व्यवहारिक हो और नेतृत्व दृढ़ इच्छाशक्ति से निर्णयों को आगे बढ़ाए, तो नीतिगत बदलाव संभव हैं। यह निर्णय सिर्फ अनुपात बदलने का नहीं, बल्कि जनसरोकारों की नब्ज पहचान कर उसे नीति में बदलने का जीवंत उदाहरण है। राज्य के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी दिशा दिखा सकती है। पीडीएस को अधिक पारदर्शी और हितग्राही केंद्रित बनाने के लिए आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल वितरण ट्रैकिंग, और ई-केवाईसी जैसी आधुनिक तकनीकों को तेजी से लागू किया जा रहा है।

कलेक्टर ने अमृत सरोवर, स्वास्थ्य केंद्र और गौशाला का निरीक्षण कर दिए दिशा-निर्देश

सिरोंज। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने आज सिरोंज क्षेत्र में भ्रमण कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों तथा क्रियान्वित शासकीय कार्यों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने सिरोंज के आईटीआई शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का भ्रमण कर जायजा लिया। उन्होंने आईटीआई के साथ-साथ पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का भी निरीक्षण किया है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक में छात्र संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण छात्रों का किस तरह आईटीआई और पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए रुझान बड़े इसके लिए विशेष कार्य करने होंगे। उन्होंने कस्तूरबा बालिका छात्रावास की बालिकाओं के लिए बारिश से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की ओर पहल करने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत पाठशाला भवन के लिए किये जा रहे कार्यो और मॉडल स्कूल में लाइब्रेरी और कंप्यूटर की सुविधा छात्रों को मुहैया हो इसके लिए विशेष कार्य करने के निर्देश मौके पर ही अधिकारियों को दिए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिरोंज के सीएम राइज स्कूल के पहुंच मार्ग में आ रही दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए छात्र-छात्राओं को लाने ले जाने की विशेष व्यवस्थाएं बनाने के लिए स्थानीय एसडीएम को निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सिरोंज के देवपुर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और श्रद्धालुगणो के लिए मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सावन माह में देवपुर मंदिर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम को बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं साथ ही साथ उन्होंने मंदिर कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव प्रस्तावों पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नवीन मंडी सिरोंज का भी निरीक्षण किया और आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही नवीन मंडी बनने के प्रस्ताव पर भी सहमति मिल सके इसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वाटरशेड में क्लस्टर में क्रियान्वित कार्यों का भी अवलोकन किया एवं नवीन कार्यों को प्रारंभ करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।

आवारा पशुओं को नपा ने पहुंचाया गौशाला में

आष्टा। शुक्रवार 25 जुलाई को नगर में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आगमन के सफाई मित्रों की टीम द्वारा नगर में विचरण कर रहे आवारा मवेशियों को पकड़कर दूरस्थ रूपेटा स्थित गौशाला में छुड़वाया गया।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनोदकुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जुलाई को नगर के नवनिर्मित पार्वती पुल अटल सेतु के लोकार्पण सहित अन्य विकास कार्यों के भूमिपूजन हेतु नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नगरागमन है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के उद्देश्य से नगर के मुख्य मार्गों पर विचरण कर रहे आवारा पशुओं को स्मार्ट केरल रेस्क्यू कैचिंग ट्रेलर वाहन के माध्यम से पकड़कर रूपेटा स्थित गौशाला में छुड़वाया गया है।

पत्रकार पर बिना जांच एफआईआर करने वाले थाना प्रभारी लाइन अटैच

रतलाम । रतलाम प्रेस क्लब के सदस्य और अधिमान्य पत्रकार दिव्यराज सिंह राठौर के खिलाफ बिना जांच के प्रकरण दर्ज करने वाले नामली थाना प्रभारी पातीराम डावरे को एसपी अमित कुमार ने लाइन अटैच कर दिया। इसके पहले गुरुवार दोपहर को पत्रकार दिव्यराज सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे प्रकरण के विरोध में रतलाम प्रेस क्लब ने पुरजोर विरोध दर्ज करवाया।

रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेशपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में रतलाम प्रेस क्लब के सदस्य दोपहर करीब 2 बजे एसपी ऑफिस पंहुचे और नारेबाजी की। यहां एसपी अमित कुमार ने पत्रकारों से चर्चा की और बात सुनी। अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि उपरोक्त मामले में साफ दिख रहा है कि पत्रकार के द्वारा बासी खाने की शिकायत करने और खाद्य विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की खबर प्रकाशित करने के पांच दिन बाद द्वेषता पूर्वक पत्रकार के खिलाफ नामली थाने में 18 जुलाई को आवेदन दिया गया। शासन का आदेश है कि अधिमान्य पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच के प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद नामली थाना प्रभारी द्वारा बिना जांच के, बिना वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दिए 18 जुलाई को ही पत्रकार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया।

तीन घंटे में हटाए गए टीआईः एसपी ने मामले को सुनकर तत्काल ही संज्ञान लेने और यदि कार्यवाही गलत हुई है तो जांच करके उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। एसपी ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मामले में जांच के आदेश भी दिए। इसके बाद शाम 6 बजे नामली थाना प्रभारी पातीराम डावरे को लाइन अटैच करने के आदेश जारी कर दिए गए।

यह है मामलाः पत्रकार दिव्यराज सिंह द्वारा 13 जुलाई को नामली के सोनगरा ढ़ाबे पर रात के वक्त दो साथियों के साथ खाना खाने पहुंचे थे। यहां पर खाना बासी था जिसकी शिकायत उन्होंने कर्मचारी और संचालक से की थी। इसका पूरा भुगतान करके बिल की मांग की। लेकिन संचालक ने बिल देने से इनकार करते हुए कर्मचारियों के साथ पत्रकार के साथ गाली गलौज और अभद्रता की थी। अगले दिन पत्रकार सिंह की तबीयत खराब हो गई और जिला चिकित्सालय में उपचार करवाया जिसमें फूड पॉयजनिंग बताई गई। पत्रकार ने खाने की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत 15 जुलाई को ग्रामीण एसडीएम को की थी जिसपर खाद्य विभाग एवं अन्य विभागों की टीम ने पंहुचकर सोनगरा ढ़ाबे पर जांच की थी। जांच की खबरें भी प्रकाशित हुई थीं। इसके बाद खुन्नस में आकर 18 जुलाई को कर्मचारी ने पत्रकार के खिलाफ गाली गलौज करने का आवेदन नामली थाने पर दिया था जिसपर एफआईआर दर्ज हुई थी।

प्रतिदिन लगेंगे राजस्व न्यायालय, पूरे दिन होगी सुनवाई-कलेक्टर

मंडला । कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए राजस्व न्यायालय प्रतिदिन लगाने का निर्णय लिया है। इसके परिपाल न में मण्डला के सभी तहसीलदार न्यायालयों में अब दैनिक आधार पर पूरे दिन राजस्व प्रकरणों की सुनवाई होगी। जिले की सभी तहसीलों में इसके लिए तहसीलदारों को निर्देश दिए जा चुके हैं। राजस्व न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई करने वाले राजस्व अधिकारियों को गैर न्यायालयीन कार्यों से मुक्त रखा जाएगा। इस प्रकार के गैर न्यायालयीन कार्यों जैसे प्रोटोकॉल, लॉ एंड ऑर्डर, भारतीय न्याय संहिता, अतिक्रमण तथा आवंटित थाना आदि कार्यों के लिए पृथक से राजस्व अधिकारियों को तैनात किया गया है। यह जानकारी कलेक्टर ने जिला योजना भवन में पत्रकार वार्ता में मीडिया संस्थान के प्रतिनिधियों को दी। कलेक्टर ने

पत्रकारों को बताया कि नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों को इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश अनुसार अनुविभाग मण्डला की मण्डला तहसील में राजस्व न्यायालय के लिए प्र. तहसीलदार श्री हिमांशु भलावी और बम्हनी तहसील के लिए नायाब तहसीलदार हीरालाल तिवारी को आदेशित किया गया है जबकि अनुविभाग मण्डला के गैर राजस्व न्यायालयीन कार्यों के लिए प्र. तहसीलदार श्री पुष्पेन्द्र पन्द्रे को लगाया गया है।

इसी प्रकार नैनपुर अनुविभाग में हरीसिंह धुर्वे तहसीलदार नैनपुर एवं सुश्री पूजा राणा नायब तहसीलदार चिरईडोंगरी न्यायालयीन कार्य में संबद्ध रहेंगे, जबकि अनुविभाग की दोनों तहसीलों के गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए श्री कैलाश प्रसाद कौल उत्तरदायी होंगे। नारायणगंज के लिए श्री संगम पटले तहसीलदार नारायणगंज तथा श्री चैनसिंह मार्को प्रभारी नायब तहसीलदार बीजाडांडी राजस्व न्यायालय के काम करेंगे, जबकि गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए श्री आलोक सोनी प्रभारी नायब तहसीलदार बबलिया को जिम्मेदारी दी गई है।इसी तरह तहसील निवास के राजस्व के लिए श्री संदीप नागोसे तहसीलदार निवास तथा गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए आलोक सोनी प्रभारी नायब तहसीलदार बबलिया को नियुक्त किया गया है।

रेनकोट नहीं मिलने से नगर परिषद कर्मचारी परेशान

नगर परिषद ने टीन शेड में साप्ताहिक हाट बाजार लगवाया, रेनकोट वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया

औबेदुल्लागंज (संवाददाता)। कार्यालय नगर परिषद औबेदुल्लागंज नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोनू चौकसे , मुख्य नगर पालिका अधिकारी किरण राहंगडाले के द्वारा दिए गए आदेश अनुसार वार्ड क्रमांक 4 स्थित साप्ताहिक हाट बाजार अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर्मचारीयो के द्वारा बाजार का निरीक्षण कर दुकान लगाए जाने एवं पार्किंग व्यवस्था हेतू आदेशित किया तथा नगर परिषद के फील्ड के कर्मचारियों को रेनकोट वितरण का कार्यक्रम भी किया गया कर्मचारीयो एवं दल के सहयोग से हाट बाजार की संपूर्ण आवश्यक व्यवस्था को पूर्ण साप्ताहिक हाट बाजार लगाया गया टीन सेट पर हाट बाजार लगाने से समस्त नगर वासियों को बाजार आने-जाने में सब्जी क्रय किए जाने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी एवं इसका लाभ समस्त नगर वासियों को होगा इस व्यवस्था में विशेष रूप से उपस्थित रहे सोनू चौकसे पूर्व मंडल अध्यक्ष , सुजीत यादव ,राजेंद्र साहू, मनोज चौरसिया को बनाए जाने में लगे कर्मचारी अधिकारी महेश मीणा राजकुमार शर्मा ,राजकुमार ,राजा दरोगा एवं समस्त कर्मचारी दल विशेष रूप से उपस्थित रहे ।

हरियाली अमावस्या पर कलेक्टर ने ज्ञानदीप स्कूल परिसर में किया पौधरोपण

मंडला। जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा हरियाली अमावस्या के अवसर पर ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान अंतर्गत आयोजित हरियाली महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने स्कूल के विद्यार्थियों और स्टाफ के साथ गमलों तथा परिसर में पौधारोपण किया। स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि हमारे बड़े-बुजुर्गों ने जिन पौधों को इस धरा पर लगाया था, आज हम उन वृक्षों की छाया पा रहे हैं। इसी तरह हमें भी अपनी भावी पीढ़ी के लिए पौधों का, रोपण करना चाहिए।उन्होंने पौधारोपण कर रहे बच्चों से इन पौधों की देखभाल करने की अपील भी की। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, ज्ञानदीप स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव श्री संजय तिवारी, सदस्य श्री मनोज फागवानी सहित स्कूल स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे।

बाल्यकालीन बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार निरंतर अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही

पूर्व राज्यमंत्री पटेल ने किया दस्तक अभियान का शुभारंभ, दस्तक अभियान के तहत एक लाख 27 हजार 133 बच्चों की होगी स्क्रीनिंग

नरसिंहपुर। पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल ने दस्तक अभियान का शुभारंभ मंगलवार 22 जुलाई को जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में दीप प्रज्जवलित कर किया। इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री श्री पटेल ने मौजूद बच्चों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें टाफी, ओआरएस के पैकेट एवं बिस्किट वितरित किए।

पूर्व राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रत्येक वर्ष जून माह में गर्मी एवं बरसात में मौसमी बीमारियों का संक्रमण अधिक बढ़ जाता है। इस संक्रमण के कारण बीमारियां फैलती हैं और अधिक लोग बीमार होते हैं। इस मौसम में जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में बीमारी से ग्रसित होने की अधिक संभावना होती है। उन्होंने कहा कि बाल एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाने और बाल्यकालीन बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से राज्य सरकार निरंतर अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिससे आम नागरिक एवं बच्चे मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। उन्होंने बताया कि दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग का अमला संक्रमित बीमारियों की पहचान कर उनका उपचार करेगी। अभियान में बीमार बच्चों को चिन्हित कर उन्हें मुख्यालय लाने और इलाज कराने की पूरी व्यवस्था टीम द्वारा की जाएगी। एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर- घर जाकर दस्तक देगी और सभी 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों की स्क्रीनिंग करेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि जिले में 22 जुलाई से 16 सितम्बर 2025 तक यह दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिले के कुल एक लाख 27 हजार 133 बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए जिले में 170 दल गठित किए हैं। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सीएचओ, एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का संयुक्त दल घर- घर जाकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का आंकलन करेगी और बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध करेगी। उक्त संयुक्त दल बच्चों की 7 प्रकार की जांच एवं स्क्रीनिंग करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बाल एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाना एवं बाल्यकालीन बीमारियों की रोकथाम करना है। अभियान के दौरान शेष छूटे हुए बच्चों एवं नवजात शिशु के लिए एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का संयुक्त दल घर- घर जाकर भेंट करेगी और सेवाएं प्रदान करेगी।

उक्त दल 5 वर्ष से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान कर रेफरल एवं प्रबंधन का कार्य करेगी। एचबीएनसी एवं एचबीवायसी की तर्ज पर उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं एवं बच्चों का चिन्हांकन व रेफरल करेगी। साथ ही 6 माह से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों का डिजिटल हीमोग्लोबियोमीटर द्वारा एनीमिया की जांच तथा प्रोटोकॉल आधारित प्रबंधन करेगी। इसके अलावा 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आयु अनुरूप विटामिन ए अनुपूरण प्रदान करेगी।

अभियान के तहत दल द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शैशव, बाल्यकालीन निमोनिया एवं डायरिया की त्वरित पहचान, प्रबंधन व रेफरल का कार्य करेगी। इसके साथ ही 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग नियंत्रण के लिए समस्त बच्चों को ओआरएस एवं जिंक टेबलेट की को- पेकिंग प्रदान कर इसके उपयोग के लिए सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देगी। सामुदाय को समुचित शिशु एवं बाल आहारपूर्ति संबंधी समझाइश भी प्रदान करेगी।

इस अवसर पर महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, अंशुल नेमा, मयंक जैन, शिवम नेमा, सोमेश श्रीवास्तव, अन्य जनप्रतिनिधि, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जीसी चौरसिया, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुनील पटेल, प्रभारी जिला चिकित्सालय डॉ. राहुल नेमा, सहित अन्य डॉक्टर, जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के अधिकारी- कर्मचारी और नागरिक व बच्चे मौजूद रहे।

गोदरेज भारत की स्वच्छ तकनीक के यूरोप को निर्यात का समर्थन करता है अपने अब तक के सबसे बड़े कार्बन कैप्चर उपकरण के साथ

मुंबई, एजेंसी। गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप के प्रोसेस इक्विपमेंट व्यवसाय को यूरोप में एक कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण सुविधा के लिए अपने अब तक के सबसे बड़े उपकरण के निर्माण और आपूर्ति का एक अंतरराष्ट्रीय आदेश प्राप्त हुआ है। यह उन्नत उपकरण, उच्च दक्षता से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने और पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो गोदरेज की क्षमताओं और भारत की सटीक भारी उपकरण निर्माण में बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। यह कॉलम गोदरेज द्वारा अब तक वितरित सभी उपकरणों से बड़ा होगा, और इसके पैमाने और जटिलता में एक नया मील का पत्थर स्थापित करेगा। वर्तमान में, इस व्यवसाय की 70 प्रतिशत आय निर्यात बाजारों से आती है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में हाल ही में आए बदलाव के साथ, कंपनी अपने निर्यात बाजारों को विश्व स्तर पर विविध बना रही है।

जब पॉडकास्टर्स बने पॅनेलिस्ट नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 3' में मचाया धमाल!

मुंबई, एजेंसी। जो अक्सर सवाल पूछते हैं, इस बार खुद सवालों के घेरे में थे! देश की सबसे वायरल आवाज़ें - जो आमतौर पर लोगों की क्लास लगाती हैं - इस शनिवार द ग्रेट इंडियन कपिल शो में खुद हॉट सीट पर बैठीं। सौरभ द्विवेदी, समदीश, कामिया जानी और राज शमानी ने कपिल शर्मा के काउच पर संभाली कमान, और जान लिया कि माइक्रोफोन के दूसरी ओर बैठना कैसा होता है! कपिल शर्मा ने मजेदार अंदाज़ में कहा, इन चारों ने लगभग हर बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले लिया है, और सबकी विशलिस्ट में एक ही नाम था - तो सोचा चारों को एक साथ ही बुला लूं! राजनीति से लेकर सेलिब्रिटी चटपटी बातों तक, ये चारों आमतौर पर कड़े सवाल पूछने और तीखी सच्चाई सामने लाने के लिए जाने जाते हैं। मगर कपिल के मंच पर माहौल कुछ और ही ज़्यादा धमाकेदार और हंसी से भरपूर होता है और फिर आई असली कहानियां!। मैदान में किए गए इंटरव्यू से लेकर जोखिम भरी रिपोर्टिंग तक, सौरभ और समदीश ने बताया एक बेहतरीन स्टोरी के पीछे की मेहनत।

एग्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लिमिटेड ने सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल किया

मुंबई, एजेंसी। भारत में वर्तमान में कार्यरत फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटरों के बीच प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस समाधानों की पेशकश में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों में से एक,एक्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लिमिटेड ने मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है। इस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में ?2 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल है, जिसका कुल मूल्य ?2600 करोड़ है। कंपनी इस निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग अपनी प्रत्यक्ष सहायक कंपनी टीइसी अबू धाबी में निवेश के लिए करेगी, ताकि टीइसी सिंगापुर और टीइसी दुबई - जो वर्तमान में कंपनी के एक कॉरपोरेट प्रमोटर, टीइसी सिंगापुर द्वारा नियंत्रित दो स्टेप-डाउन सहायक कंपनियां हैं - के अधिग्रहण की आंशिक भुगतान राशि को वित्तपोषित किया जा सके। यह लेनदेन आंतरिक पुनर्गठन समझौते की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है। शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।

आईएएस अधिकारी गोविंद जायसवाल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा

नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2007 बैच के आईएएस अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें श्री जायसवाल का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 11 अक्टूबर, 2025 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाएगा। जायसवाल जुलाई 2023 से उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 12 अक्टूबर, 2020 को अपनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति शुरू की, जब उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया। जुलाई 2023 में, भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए पैनल में शामिल होने के बाद, उन्हें उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया, और उनकी संयुक्त केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि 11 अक्टूबर, 2025 को समाप्त होगी। इस नवीनतम विस्तार से जायसवाल को अक्टूबर 2027 तक अपना पद जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

इंदौर में फर्जी रजिस्ट्री का 100 करोड़ का खेल, दशहरा मैदान तक की संदिग्ध रजिस्ट्री, सब पर होगी एफआईआर

इंदौर। इंदौर में फर्जी रजिस्ट्री के जरिए संपत्ति हड़पने का सौ करोड़ से ज्यादा का खेल सामने आया है। यह खुलासा और इस खेल के होने की भी अलग ही कहानी है। इसमें पंजीयन विभाग के रिकार्डकीपर, निगम के कर्मचारी और खाली पड़े प्लाट पर कब्जा करने वालों की पूरी सांठगांठ सामने आई है।

इस मामले की कलेक्टर आशीष सिंह ने गोपनीय रूप से जांच कराई तो ऐसी एक नहीं 20 रजिस्ट्रियां फर्जी निकली और कुछ संदिग्ध भी। संदिग्ध रजिस्ट्री में इंदौर के चर्चित दशहरा मैदान के सर्वे नंबर के भी कागज है। अब जांच के बाद कलेक्टर ने इस पूर खेल में शामिल सभी पर केस दर्ज करने के लिए मामला पंढ़रीनाथ थाने भेजा है।

इंदौर फर्जी रजिस्ट्री के खेल का खुलासा बीते साल अगस्त-सितंबर 2024 में मुंबई में रहने वाले हस्तीमल चौकसे की एक शिकायत से हुआ। दअसल चौकसे हर साल एक बार इंदौर आते हैं और निगम में सभी अपने टैक्स भरते हैं।

जब वह बीते साल टैक्स भरने आए तो बताया गया कि जोन 3 में शिवविलास पैलेस का प्लाट तो उनके नाम पर है ही नहीं। इस पर वह चौंक गए। उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर, निगमायुक्त और पंजीयन विभाग में की। कलेक्टर ने वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा को इसकी जांच का जिम्मा दिया।

जांच की चौंकाने वाली बात आई

जांच में सामने आया कि इस प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री रिकार्ड रूम में मौजूद है और इसी फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर निगम में इस प्लाट का नामांतरण दूसरे नाम पर कर लिया गया। इसमें भी कहानी पता चली कि इस प्लाट पर कचरा फैले की शिकायतें हुई तो निगम का कर्मचारी वहां गया तो उसे पता चला यहां कोई नहीं आता सालों से यह खाली है।

इसके बाद उसने सांठगांठ की और इसकी फर्जी रजिस्ट्री रिकार्ड रूम में बनवाकर रखी और फिर इसी आधार पर प्लाट का नामांतरण अपने नाम करा लिया। इसके बाद इसे बेचने की साजिश की गई। इस पर कलेक्टर ने थाने में केस दर्ज कराया। साथ ही दीपक शर्मा को इस तरह के सभी दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा गया। इसमें पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई और इस सभी रजिस्ट्री की जांच की तो इस तरह की 20 रजिस्ट्री फर्जी पाई गई। इसमें से 18 के दस्तावेज जुटाकर पंढरीनाथ थाने पर केस दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया है।

जांच में इन संपत्तियों को लिया गया...

नैनोद का सर्वे नंबर 294/1
चौहानखेड़ी सर्वे नंबर 192/1
मित्रबंधु नगर सर्वे 1087, 1088, 1092 व अन्य
न्यायनगर प्लाट 208
बिहाड़िया सर्वे 3
बिहाडिया सर्वे नंबर 82/2, 84
गोकन्या महू सर्वे नंबर 72, 190, 191, 181/1, 123, 184, 185
पिपल्याहाना सर्वे नंबर 213/1
मूसाखेड़ी सर्वे नंबर 461/3,
पालाखेड़ी सर्वे नंबर 1
बुढ़ानिया सर्वे नंबर 162/3/1, 161
प्लाट 293 उषानगर
खजराना सर्वे नंबर 664/2
शिवविलास पैलेस प्लाट
छोटा बांगड़दा सर्वे नंबर 103/1/35
मनोरमागंज प्लाट 481
उषा नगर दशहरा मैदान भूखंड 293
नीर नगर भूखंड 84
छोटा बागंड़दा सर्वे 103/3
भिचौली हप्सी के सर्वे नंबर ?, 30/1

इस तरह किया गया पूरा खेल

इस पूरे खेल में शामिल लोगों ने पंजीयन विभाग के रिकार्ड रूम प्रभारी मर्दन सिंह रावत के साथ मिलकर खेल किया। इसमें रिकार्ड रूम से असली दस्तावेज हटाकर फर्जी दस्तावेज रख दिए गए। मूल रजिस्ट्रियां हटाकर फर्जी रजिस्ट्रियां लग दी गई हैं। इसमें फर्जी दस्तावेज थे, अंगूठे के फर्जी निशान थे। जांच समिति को यह मामला अंगुष्ठ पंजी से पकड़ में आया क्योंकि जिन जमीनों और संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्रीयां तैयार की गई उनकी मूल अंगूष्ठ पंजी फाड़ दी गई थी।

कोरोना काल में बनाए यह दस्तावेज

जांच में सामने आया है कि जिन संपत्तियों और जमीनों की फर्जी रजिस्ट्रीयां तैयार की गई यह सभी फजी रजिस्ट्री कोरोना काल में की गई है जब पंजीयन कार्यालय बंद था। इस समय का फायदा उठाकर इस कृत्य में लिप्त अधिकारी/कर्मचारियों ने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। फिलहाल 27 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच हुई।

भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाएगा एफटीए, देगा वैश्विक मंच

टेक्सटाइल और शिल्प कारोबार को नई उड़ान

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत और ब्रिटेन ने कारोबारी रिश्तों में नया अध्याय लिखते हुए गुरुवार को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से वैश्विक बाजार में भारतीय महिलाओं को बड़ा फायदा मिल सकता है। यह समझौता हथकरघा, पारंपरिक शिल्प, टेक स्टार्टअप और स्वच्छ निर्माण जैसे क्षेत्रों में काम कर रहीं महिलाओं को वैश्विक बाजार से जोड़ने का रास्ता खोलेगा। इससे उन्हें न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता और कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि यूके के 23 अरब डॉलर के बाजार में कपड़ा, चमड़ा और जूते जैसे उत्पाद शुल्क मुक्त भेजने की सुविधा भी मिलेगी। इस कदम से भारतीय महिलाएं बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे देशों की कंपनियों से बराबरी की होड़ में उतर सकेंगी। भारत का जीवंत वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र महिलाओं के कौशल पर टिका है,फिर चाहे वह कांचीपुरम, भागलपुर, जयपुर या वाराणसी की बुनकर, कढ़ाई करने वाली, रंगाई करने वाली या डिजाइनर हों। इस एफटीए से अब वे वैश्विक फैशन और डिजाइन की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर पाएंगी।

महाराष्ट्र और आस-पास के इलाकों में महिलाओं की हाथ से बनाई जाने वाली कोल्हापुरी चप्पलें अब यूके के प्रीमियम बाजार में बगैर शुल्क के बिक सकेंगी। इससे इनका ब्रांड बढ़ेगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी,आय बढ़ेगी और टिकाऊ चमड़े के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

इस एफटीए से देष में महिलाओं के चलाए जा रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईजी) को अब सरल नियम,प्रशिक्षण समर्थन और व्यापार वित्त में मदद मिलेगी। गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के क्लस्टर अब अधिक प्रतिस्पर्धी और यूके के लिए तैयार होंगे। चाहे वो वाराणसी के करघे हों, हैदराबाद की डिजिटल प्रयोगशालाएं, राजस्थान के शिल्प समूह हो या फिर बंगलूरू के स्टार्टअप यह समझौता महिलाओं को वैश्विक व्यापार के केंद्र में लाता है। यह सिर्फ शुल्क में कटौती नहीं, समझौते के तहत ब्रिटेन की वाहन कंपनियों को भारत में सिर्फ बड़े पेट्रोल-डीजल और महंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही शुल्क में रियायत मिलेगी। घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश कंपनियों की मध्यम-छोटी कारों और कम कीमत वाले ईवी पर शुल्क छूट नहीं दिया जाएगा। समझौते के पहले पांच साल में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी।

मुकेश अंबानी ने जितना जिंदगीभर कमाया उतना लैरी एलिसन सात महीने में ही कमा गए

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में एक स्थान फिसल गए हैं। गुरुवार को उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब दो फीसदी गिरावट आई। इससे अंबानी की नेटवर्थ में .1.36 अरब की गिरावट आई। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक अंबानी .102 अरब की नेटवर्थ के साथ

दुनिया के अमीरों की लिस्ट में एक स्थान फिसलकर अब 18वें नंबर पर आ गए हैं। मेक्सिको के अरबपति कार्लोस स्लिम (.103 अरब) उनसे आगे निकल गए हैं। अंबानी की नेटवर्थ में इस साल .11.1 अरब की तेजी आई है जबकि कार्लोस की नेटवर्थ 23.3 अरब बढ़ी है। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की नेटवर्थ में गुरुवार को 19.5 अरब डॉलर की गिरावट आई। वह 354 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं लेकिन इस साल उनकी नेटवर्थ में 78.6 अरब डॉलर की गिरावट आई है। इस बीच ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन की नेटवर्थ हाल में तेजी से बढ़ी है। उनकी नेटवर्थ में इस साल 101 अरब डॉलर की तेजी आई है और वह 293 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में ऐमजॉन के को-फाउंडर जेफ बेजोस 253 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क जकरबर्ग (251 अरब) चौथे, स्टीव बालमर (.175 अरब) पांचवें, लैरी पेज (.173 अरब) छठे, सर्गेई ब्रिन (.162 अरब) सातवें, बर्नार्ड अरनॉल्ट (.157 अरब) आठवें, जेंसन हुआंग (.151 अरब) नौवें और वॉरेन बफे (.146 अरब) दसवें नंबर पर हैं।

जल्द पूरे करें काम, अगस्त में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक

भोपाल। अगर बैंक संबंधित कोई भी काम है तो फटाफट निपटा लें क्योंकि जुलाई की तरह अगस्त महीने में 15 दिन बैंक बंद रहने वाले है। इन अवकाशों में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी के साथ शनिवार (दूसरा व चौथा) और रविवार शामिल है। बैंक बंद के चलते चेकबुक पासबुक समेत कई बैंकिंग संबंधित काम प्रभावित हो सकते है, हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, हर महीने के दूसरे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। जबकि हर रविवार को साप्ताहिक अवकाश भी होता है। त्योहारों पर बैंकों में काम नहीं होता। भारत में बैंक की छुट्टियों में राष्ट्रीय अवकाश (राजपत्रित अवकाश) व सरकारी अवकाश (राज्य/केंद्र) शामिल हैं। राज्य सरकार की छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जबकि केंद्र सरकार की छुट्टियाँ पूरे देश में एक जैसी रहती हैं। क्षेत्रीय छुट्टियां किसी विशेष राज्य या क्षेत्र से संबंधित होती हैं। एक राज्य में किसी दिन अवकाश होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्य में भी छुट्टी होगी।

किस-किस तारीख को बंद रहेंगे बैंक

3 - केर पूजा , त्रिपुरा (रविवार)

8 - सिक्किम और ओडिशा में टेंडोंग लो रम फाट त्योहार, 9- रक्षाबंधन, 10 - रविवार, 12 - दूसरा शनिवार, 13- मणिपुर , देशभक्त दिवस, 15- स्वतंत्रता दिवस, 17- रविवार, 16 - जन्माष्टमी , पारसी नव वर्ष गुजरात , महाराष्ट्र, 24 -रविवार, 26 -गणेश चतुर्थी कर्नाटक और केरल (चौथा शनिवार), 27- गणेश चतुर्थी आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना, 28- नुआखाई ओडिशा, पंजाब , सिक्किम, 31 रविवार बैंक की छुट्टियों के दौरान कस्टमर्स ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते है, क्योंकि यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंगजैसी डिजिटल सेवाओं पर बैंक हॉलीडे का कोई असर नहीं होता है।

नेट बैंकिंगः बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मनी ट्रांसफर, बिलों का भुगतान और बैलेंस चेक की सुविधा उपलब्ध होती है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसः पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक सुरक्षित तरीका है आपको केवल यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि का इस्तेमाल करना होता है।

मोबाइल बैंकिंगः स्मार्टफोन पर बैंक की मोबाइल एप के जरिए आप कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट आदि।

एटीएम उपयोगः पैसे निकालने, बैलेंस चेक करने और मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए एटीएम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। एटीएम में कार्डलेस कैश विदड्रॉल जैसी सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक जाने से पहले अपनी स्थानीय बैंक शाखा से छुट्टियों के बारे में पता कर लें, क्योंकि भारत में हर राज्य में छुट्टियां अलग-अलग होती हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन में करेंगे रेल कोच निर्माण इकाई का भूमिपूजन

भोपाल। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 अगस्त को रायसेन में 1800 करोड़ रूपए के निवेश से प्रारंभ होने वाली रेल कोच निर्माण इकाई का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड बैंगलुरु के चेयरमेन, मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय, निदेशक रेल एवं मेट्रो राजीव गुप्ता, महाप्रबंधक बीईएमएल चंद्रशेखर और ईडी ओ.पी. सिंह ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जानकारी दी गई कि बीईएमएल द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, रायसेन जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ सम्पर्क कर रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के ग्राम उमरिया में अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री के शिलान्यास की आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इस इकाई के फलस्वरूप 1575 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। इकाई को आवंटित शासकीय भूमि को रेल लाइन से जोड़ने के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बीईएमएल के पदाधिकारियों को मध्यप्रदेश में विभिन्न सेक्टर्स में आ रहे निवेश की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रायसेनजिले में रेल कोच निर्माण इकाई प्रारंभ होने से स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भेंट के दौरान प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

पंकज त्यागी भोपाल के डीआरएम बने, भारतीय रेलवे ने विभिन्न जोनों में 32 नई नियुक्ती की

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न जोनों में 32 वरिष्ठ अधिकारियों को मंडल रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया। पंकज त्यागी को भोपाल का डीआरएम बनाया गया है।

पंकज त्यागी (आईआरएसई), एनएफएचएजी रेलवे बोर्ड, को डीआरएम भोपाल पश्चिम मध्य रेलवे के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वे देवाशीष त्रिपाठी (आईआरएसएमई) का स्थान लेंगे। विनोद कुमार (आईआरएसई), जो वर्तमान में आरएलडीए में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दानापुर, पूर्व मध्य रेलवे का डीआरएम नियुक्त किया गया है। वे जयंत कुमार चौधरी (आईआरएसई) का स्थान लेंगे। दिव्यकांत चंद्राकर (आई आर एसई), एनएफएजी मध्य रेलवे को डीआरएम त्रिवेंद्रम दक्षिणी रेलवे के पद पर तैनात किया गया है। उन्होंने मनीष थपलियाल (आईआरएसए मई) का स्थान लिया।

संग्रह मौर्य (आईआरएसई), एनएफएचएजी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को डीआरएम मुरादाबाद उत्तर रेलवे के पद पर नियुक्त किया गया है। वह राजकुमार सिंह (आईआरएसईई) का स्थान लेंगे।

किरेन्द्र नराह (आईआरएसई), एनएफएचएजी दक्षिण पूर्व रेलवे को डीआरएम कटिहार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के पद पर नियुक्त किया गया है। वह सुरेन्द्र कुमार (आईआरएसईई) का स्थान लेंगे।

ओम प्रकाश मीणा (आईआरएसई), एनएफएचएजी पूर्वी रेलवे, को डीआरएम आईवीअदुरई दक्षिणी रेलवे के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वे शरद श्रीवास्तव (आईआरटीएस) का स्थान लेंगे। बालक राम नेगी (आईआरएसई), एनएफएचएजी उत्तर रेलवे, को एम.एस. अनबालागन (आईआरएसएस) के स्थान पर डीआरएम तिरुचिरापल्ली दक्षिणी रेलवे के पद पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

रवि कुमार गुप्ता (आईआरएसई), एनएफएचएजी, जो वर्तमान में अध्यक्ष आरआरबी, चंडीगढ़ के रूप में कार्यरत हैं, को सुमित नरूला (आईआरएसएमई) के स्थान पर डीआरएम आद्रा दक्षिण पूर्व रेलवे के रूप में स्थानांतरित किया गया है।गगन गोयल (आईआरएसई), एनएफएचएजी उत्तर पश्चिम रेलवे, को डीआरएम आगराउत्तर मध्य रेलवे के पद पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वे तेज प्रकाश अग्रवाल (आईआरएसईई) का स्थान लेंगे।

प्रदीप कुमार मोहंती (आईआरएसई), एनएफएचएजी ईस्ट कोस्ट रेलवे को स्थानांतरित कर डीआरएम अलीपुरद्वार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।अश्विनी श्रीवास्तव (आईआरटीएस), एनएफएचएजी, जो वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को डीआरएम समस्तीपुरपूर्व मध्य रेलवे के पद पर विनय श्रीवास्तव (आईआरएसएमई) के स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। वेद प्रकाश (आईआरटीएस), एनएफएचएजी रेलवे बोर्ड, को डीआरएम अहमदाबाद पश्चिम रेलवे के पद पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

करप्शन का सारथी, मनमौजी प्रणाली

सरयूसुत मिश्रा

यह विवाद रिटायर्ड आईएएस, सिया के अध्यक्ष, विभाग के प्रमुख सचिव एवं सदस्य सचिव के बीच नियमों के उल्लंघन, भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुआ था। जो विभाग की असली ताकत साबित करने में बदल गया। पहली हार सिया चेयरमैन की हुई जब उनके कक्ष में तालाबंदी की गई। इसका आरोप प्रमुख सचिव और सदस्य सचिव पर लगा। अब इन दोनों अफसरों की हार हुई है। सिटिंग और रिटायर्ड आईएएस अफसरों की इस जंग में प्रशासन और पर्यावरण की सबसे बड़ी हार हुई है। बिना सिया की स्वीकृति के जिन प्रकरणों को मंजूरी दी गई है, उसमें सीधा नियमों को तोड़ा गया है। आरोप के मुताबिक इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। इसकी शिकायत राज्य और केंद्र सरकारों को की गई है। अब तो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। यह पूरा घटनाक्रम जब उछला तब राज्य के सीएम विदेश प्रवास पर थे। लौटने के बाद पूरी जानकारी के उपरांत ट्रांसफर का यह एक्शन यही बताता है कि, प्रथम दृष्टया इन दोनों अफसरों को दोषी माना गया है। दोनों ट्रांसफर में अपग्रेडेशन ही दिखाई पड़ता है। एक अधिकारी को राजभवन में प्रमुख सचिव बना दिया गया है तो दूसरे को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर काम का बोझ कम कर दिया गया है। राज्य की ट्रांसफर पॉलिसी में भले ही राजभवन के प्रमुख सचिव का पद उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता हो लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया में शासन, राज्यपाल के नाम से ही संचालित होता है। यही वजह है कि, उनके प्रमुख सचिव की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती। राजभवन में भी सीनियर अफसर का नहीं टिक पाना भी कई सवाल खड़े करता है। राज्य सरकार और राजभवन के बीच संतुलन के इस पद पर पदास्थापना में अस्थिरता, प्रशासनिक चंचलता दिखाती है। सिया में उठा विवाद ट्रांसफर के साथ भले ही धीमा पड़ गया हो लेकिन इससे उन सवालों का समाधान नहीं हुआ है, जो सिया अध्यक्ष द्वारा लिखे पत्र में उठाए गए थे। अगर पर्यावरण की मंजूरी के प्रोजेक्ट में नियमों का उल्लंघन हुआ है? भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं? तो फिर ट्रांसफर नहीं बल्कि दंडात्मक कार्यवाई जरूरी है। ट्रांसफर के जरिए नई पदस्थापना पुरानी गड़बड़ियों और गलतियों को मिटा नहीं सकता है। सरकारों में यह प्रवृत्ति पूरे सिस्टम को प्रदूषित कर रही है। जो भी ऐसे विवाद आते हैं, पहले तो उसको सुलटाने की कोशिश की जाती है। जब मामला सीमा पार चला जाता है तो फिर ट्रांसफर करके उसको दबा दिया जाता है। यही सिया के विवाद में भी अब तक दिखाई पड़ा है, जो प्रशासनिक दृष्टि से सही कदम नहीं कहा जाएगा।

कोई भी गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन प्रकाश में आने के बाद व्यक्ति आधारित मामला नहीं बचता बल्कि इसको सिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए। जो भी एक्शन हो वह सुधार की दृष्टि से हो। जिससे कि, भविष्य में ऐसी गलतियां दोहराई ना जा सके। नियमों को तोड़ने की किसी भी लेवल पर कोई ताकत ना बचे। मनमौजी प्रशासन प्रणाली ही करप्शन की सारथी होती है। प्रशासन की प्रक्रिया नियम के अनुरूप हो ना कि, ताकतवर अफसर की मौज उसे संचालित करने का दुस्साहस कर सके। पर्यावरण मंजूरी का विषय केवल प्रशासनिक गड़बड़ी का नहीं है बल्कि इससे आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। पर्यावरण से जुड़ा कोई भी निर्णय अगर नियमों के विपरीत होगा तो इससे पर्यावरण को चोट पहुंचेगी। जो अंततः आम जनजीवन को प्रभावित करेगा। इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से ऐसे मामलों में ट्रांसफर की नीति अपनाकर नियम तोड़ने और कमाने के आरोपों को दबाया जाता है उससे तो यही कहा जा सकता है कि, 'नियम तोड़ो, कमाओ और ट्रांसफर का लाभ उठाकर अच्छी पोस्टिंग पाओ' की योजना सबसे' लाभकारी है। नियम प्रक्रियाओं की अनदेखी कर प्रशासन की मनमौजी प्रणाली शासन के पूरे सिस्टम पर हावी हो गई है। चपरासी से लेकर विभाग अध्यक्ष तक सब की सिस्टम में भूमिका परिभाषित है, लेकिन हर विभाग, विभागाध्यक्ष के मौज के मुताबिक चलता है। अगर किसी स्तर के किसी व्यक्ति ने नियम कानून बताने की कोशिश की तो उसे अपमानजनक व्यवहार से गुजरना पड़ता है। आजकल तो ताकतवर पदों पर आसीन अफसरों का संवाद और भाषा भी शिष्टाचारके अनुरूप नहीं दिखाई पड़ती। समाचार पत्रों में राष्ट्रीय हरिहर नाट्य समारोह के विज्ञापनों में मनमौजी शासन प्रणाली सार्वजनिक रूप से शासन द्वारा ही प्रकट की गई है। संस्कृति विभाग के एक ही कार्यक्रम को दो विज्ञापनों में बताया गया है।एक संस्कृति विभाग का है तो दूसरा इसी विभाग के अंतर्गत वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम का है। एक कार्यक्रम में अतिथि बताए गए हैं, दूसरे में कोई अतिथि नहीं है। समुद्र मंथन पर आधारित इस इवेंट के महासंदेश अगर राज्य के लिए इतना जरूरी थे? तो अब से पहले किसी भी शासक ने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? जहां तक समुद्र मंथन का सवाल है, सरकार में तो यह सतत चलता रहता है। इस मंथन में एक तरफ नियम प्रक्रिया होती है तो दूसरी तरफ शासक के मनमौजी फरमान होते हैं। दोनों के मंथन में जो अमृत निकलता है, वह तो सिस्टम के देव पी जाते हैं। मंथन से निकला विष कोई भी पीना नहीं चाहता लेकिन कभी कभार किसी छोटे-मोटे को दंड मिल जाता है। विष सिस्टम में फैलता रहता है। इसी के चलते पूरा सिस्टम विषैला हो जाता है। विषैले सिस्टम का नुकसान अंततः लोकतंत्र के मलिक आम नागरिक को ही उठाना पड़ता है।

एक कवि का व्यंग्य मौजू है। जिसमें कवि कहता है कि, 'एक बॉस अपने अधीनस्थ को डांटते हुए कह रहा है कि...

तुम गधे हो, मक्कार, कामचोर, बेईमान हो।

तो अधीनस्थ धीरे से जवाब देता है, सर आप ठीक कह रहे हैं। 'सर आप हमारे बॉस हैं'। जो विशेषण लगाए गए हैं, उसमें कौन, किसका बॉस है यह तय करना मुश्किल है।

आँगनबाड़ियों में खेल से सीखने की शक्ति को बढ़ावा

छिंदवाड़ा। एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) की 50वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में, की एजुकेशन फाउंडेशन (केईएफ) ने एक विशेष कार्यक्रम 'बचपन का त्यौहार' का आयोजन किया, जिसने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आनंदमय शिक्षा का परिपोषण करने वाले स्थान के रूप में आँगनबाड़ियों का उत्सव मनाया।मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव, श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आईएएस, ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया। इस कार्यक्रम में 'बचपन का त्यौहार' नामक एक कहानी-पुस्तक का आधिकारिक विमोचन भी हुआ, जो आँगनवाड़ियों के देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के आनंददायक केंद्रों के रूप में जीवंत विकास को दर्शाती है। श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश, ने कहा, खेल सीखने का सबसे अच्छा तरीका है और बच्चे यह बिना जाने ही सीख जाते हैं। यह उनके साथ रहता है और खासकर छोटे बच्चों के लिए, यह उनके बचपन का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है और माता-पिता के लिए भी इसमें शामिल होने का एक बेहतरीन तरीका है। हमारे आँगनवाड़ी केंद्र इसे और भी बेहतर बना सकते हैं, ताकि हर बच्चा फल-फूल सके।

चौरई एसडीएम ने किया मूंग खरीदी केंद्रों का निरीक्षण,

आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिये निर्देश

छिन्दवाड़ा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री प्रभात मिश्रा द्वारा आज चौरई क्षेत्र में मूंग उपार्जन कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने भारतद्वाज वेयरहाउस लिखड़ी खटकर खरीदी केंद्र का दौरा किया, जहां किसानों की संख्या को देखते हुए वेयरहाउस प्रबंधक को एक अतिरिक्त ग्रेडर मशीन लगाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने समिति प्रबंधक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि केवल एफएक्यू श्रेणी की उपज की ही खरीदी की जाए। वहीं वेयरहाउस में बिजली वोल्टेज से संबंधित समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को तत्काल सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत एसडीएम मिश्रा ने कृपाशु वेयरहाउस बरेलीपार का भी भ्रमण किया तथा खरीदी कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश समिति प्रबंधकों को दिए।

पवन कड़ोपे ने यूजीसी नेट की परीक्षा में पाई सफलता

छिन्दवाड़ा। शासकीय महाविद्यालय बिछुआ के अंग्रेजी विभाग के छात्र ने यूजीसी नेट की परीक्षा में सफलता पाई अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ.अजीत डेहरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र पवन कड़ोपे ने वर्ष 2025 जून माह की यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ विभाग की ही दिव्यानी ठाकुर ने नेट परीक्षा से ही पीएचडी इंट्रेंस परीक्षा पास की है। घाटकामठा निवासी पवन ने अपनी सफलता का श्रेय अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ.अजीत डेहरिया पिता मीतराम कड़ोपे, माता श्रीमती प्रेमवती कड़ोपे एवं मामा झमकलाल सरेयाम को दिया है। छात्र-छात्रा की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉ.आर.पी.यादव एवं समस्त महाविद्यालय परिवार ने शुभकामनाएं दी।

वांछित इनामी स्थायी वारंटियो को विभिन्न स्थानों से किया गिरफ्तार

छिंदवाड़ा। जिला पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देशन में जिले में विशेष टीम गठित कर माननीय न्यायालयो द्वारा जारी स्थायी / गिरफ्तारी वारंटियो की धरपकड़ कर न्यायालय में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है! इसी परिपेक्ष्य में आज दिनांक 24-07-2025 को कुल 02 फरार स्थाई वारंटियों की तामीली में बड़ी सफलता हाथ लगी है,थाना चौरई अंतर्गत धारा 6(2)क दहेज प्रतिशेध अधिनियम के 01 वर्ष पुराने में 1000/- रूपये का इनामी फरार स्थायी वारंटी भरत पिता पूनाराम डेहरिया निवासी टी.वी टावर,हंशनगर थाना देहात, थाना देहात अंतर्गत धारा 138 ह. ढ्ढ.ष्टञ्ज के 02 वर्ष पुराने में 5,000/- रूपये का इनामी फरार स्थायी वारंटी अखिलेश राय पिता झलकन राय उम्र 48 वर्ष निवासी परासिया आराधना विद्यालय के पीछे थाना परासिया, इस तरह इन स्थायी फरार वारंटियों को मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया, स्पेशल धरपकड़ पुलिस टीम उनि राजेश साहू सउनि नितेश ठाकुर प्र.आर श्याम ठाकरे खेमचंद अहिरवार रविन्द्र ठाकुर, नितिन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही, विशेष पुलिस टीम द्वारा वांरटियों की धरपकड/गिरफतारी लगातार जारी रहेगी !

7 दिनों में शत प्रतिशत बुक वितरण एवं यूनिफॉर्म की राशि के लिए खाते वेरीफाई कराएः कलेक्टर

छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कक्षा 1 से 8 तक के प्राइवेट स्कूल के नामांकन की जानकारी लेते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए और प्राइवेट स्कूलों की बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौगांव के शासकीय एवं गौरिहार के प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। यह बैठक गुरूवार को छतरपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान डीपीसी अरुण शंकर पांडेय सहित बीईओ एवं बीआरसी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बारीगढ़, बड़ामलहरा एवं बक्सवाहा को विशेषरूप से टेस्ट बुक के 1 हफ्ते के भीतर शतप्रतिशत वितरण कराने के निर्देश दिए। साथ ही यूडाइस पर कक्षा 9 से 12 के छात्रों के प्रमोशन स्टेटस में खराब प्रगति पर एवं सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें बंद ना करने पर डी ग्रेड में होने पर लवकुशनगर बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सात दिवस में छात्रों को दी जाने वाली यूनिफॉर्म के लिए बच्चों बैंक खाता वेरीफाई कराने और शत प्रतिशत साइकिल वितरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने छतरपुर बीआरसी द्वारा बच्चों के खाते वेरिफिकेशन में खराब प्रगति पर शोकॉज जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही छतरपुर बीआरसी को स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक हफ्ते में साइकिल वितरण में प्रगति में सुधार करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।

जिले को दो दिन में होगी 4000 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति

वितरण केंद्रों पर कलेक्टर द्वारा लगातार की जा रही मॉनिटरिंग

छिन्दवाड़ा। खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशन में जिले के सभी यूरिया वितरण केंद्रों पर राजस्व, कृषि, सहकारिता और मार्कफेड विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमें सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में लगभग 2500 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है और अगले दो दिनों में 02 रैक से 4000 मीट्रिक टन यूरिया और प्राप्त हो जाएगा। इनमें चंबल की रैक से 1800 मीट्रिक टन और कोरोमंडल की रैक से लगभग 2200 मीट्रिक टन यूरिया शामिल है। इसके साथ ही 05 अन्य रैक ट्रांजिट में हैं, जिससे जुलाई माह में लगभग 10000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया जिले को प्राप्त होगा। वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु सभी मार्कफेड गोदामों पर अनुविभागीय अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर 3-4 वितरण काउंटर संचालित करवा रहे हैं। किसानों को संयम के साथ वितरण केंद्रों पर पहुंचने की अपील की गई है ताकि लाइन में समय न लगे और उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से खाद मिल सके। प्रशासन द्वारा किसानों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 2 बैग यूरिया का ही प्रयोग करें ताकि उपज में लाभ के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे।

जिले में यूरिया कालाबाजारी पर लगातार की जा रही कार्यवाही

इस वर्ष 05 एफआईआर दर्ज, 23 लाइसेंस निरस्त और 37 किए गए निलंबित कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार जिले में यूरिया उर्वरक की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में जिले के लावाघोघरी थाना अन्तर्गत मैनीखापा क्षेत्र के विकास कृषि केंद्र के संचालक श्री विकास सूर्यवंशी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया का विक्रय किया।उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष अब तक जिले में यूरिया से संबंधित अवैध गतिविधियों पर 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त 23 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और 37 लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। जिले के सभी निजी विक्रेताओं के यहां कृषि विभाग के विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि उनका विक्रय पूरी तरह निगरानी में हो। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी विक्रेता निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलता पाया गया या किसी अन्य उर्वरक की टैगिंग करता मिला, तो उसके विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक मूल्य वसूली या अनियमितता की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों या नियंत्रण कक्ष को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

भाजपा नेताओं से दिल्ली में मिले संदीप रघुवंशी

छिंदवाड़ा। भाजपा नेता संदीप रघुवंशी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर है, उन्होने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल.सन्तोष से मिले एवं संगठन के संबंध में चर्चा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले एवं जिले के कृषि एवं यूरिया के संबंध में चर्चा की, जिले में लगातार कृषि का रकबा बढ रहा है, जिससे जिले का किसान समृद्ध हो रहा है। वे मथुरा की सांसद हेमा मालनी से भी मिले एवं छिंदवाड़ा आने का आमन्त्रण दिया, उन्होने बताया छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में पर्यटन को लेकर स्टे होम एवं पातालकोट की जानकारी दी।

राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की अहम भूमिकाः अनुज पाठकर

विद्यार्थी परिषद का 77 वां स्थापना दिवस

परासिया। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन जो पिछले सात दशकों से छात्र हित एवं राष्ट्र हित में कार्य करते आ रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 77वां स्थापना दिवस जिससे सम्पूर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया है। एबीवीपी का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना है और छात्रों के व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। एबीवीपी छात्रों के बीच राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना का विकास करता है और सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियो माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। एबीवीपी छात्रों की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुँचाता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करता है। विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अभाविप परासिया नगर इकाई द्वारा शासकीय पेंचवेली महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं नगर कार्यकारिणी घोषणा का आयोजन किया गया। जिसमे मुख्य रूप से परासिया एस डी एम पुष्पेंद्र निगम, अनुज पाटकर एवं अभाविप महाकोशल प्रांत सह संयोजक प्रफुल्ल तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। नगर कार्यकारिणी को भंग कर सत्र 2025ङ्क26 के लिए अभाविप परासिया नगर की नवीन कार्यकारिणी की की घोषणा की जिसमे नगर अध्यक्ष के रूप में डॉ. पवन नाग एवं नगर मंत्री के रूप में श्री दीपांशु यादव को पुनःनिर्वाचित किया गया। शेष नगर कार्यकारिणी जिसमे नगर सहमंत्री रितु प्रजापति खुशी विश्वकर्मा प्रद्युम्न भार्गव पार्थिव सूर्यवंशी जी को नियुक्त किया गया।

रावनवाड़ा के खदान कर्मचारी की हृदयघात से मौत

चिकित्सकों पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप , इंटक ने किया विरोध प्रदर्शन, जीएम ने सीएमओ का किया तबादला

परासिया। पेंच क्षेत्र के रावन वाड़ा मे सब स्टेशन में काम करने वाले खदान कर्मचारी अशोक डेहरिया (57 वर्ष) को गुरुवार सुबह हृदयाघात होने पर केंद्रीय चिकित्सालय बडकुही ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। जिसके बाद मृतक की पत्नी निर्मला डेहरिया और उसके तीनों पुत्र तथा इंटक संगठन के कार्यकर्ताओं ने चिकित्सालय में सीएमओ और दो चिकित्सकों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर इंटक के अध्यक्ष एवं विधायक सोहन वाल्मीकि भी पहुंचे। घटना को लेकर क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक शशीधरन चिकित्सालय आए लेकिन उनसे विधायक सोहन बालमीक ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का तबादला नहीं किया जाता है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और शव को नहीं ले जाने दिया जाएगा। इस बात की सूचना मिलने पर फिर सवा ग्यारह बजे महाप्रबंधक अनूप हजूरा आए। उन्होंने चिकित्सकों की गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी मांगी और और जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयश्री राय का तबादला करने की बात कही, तब जाकर विरोध प्रदर्शन शांत हुआ और फिर उसके बाद पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

2013 में हुआ था हृदयाघात घात

जानकारी के अनुसार अशोक डेहरिया पूर्व में विष्णुपुरी भूमिगत कोयला खदान में एसडीएल हेल्पर के पद पर कार्यरत थे। गत वर्ष 2013 में हृदयाघात होने पर अशोक डेहरिया को खदान के भीतर की बजाय ऊपर सरफेस में नौकरी दी गई थी। जिसके बाद से अशोक डेहरिया रावनवाड़ा में नौकरी कर रहा थे।

फिट करने के लिए डाक्टर ने लिए 600 रुपए

निर्मला डेहरिया ने महाप्रबंधक को यह भी बताया कि उनके देवर, जो कि बीजी साइडिंग में कार्यरत है और अभी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ दिनों पूर्व अस्पताल में पीएमई कराने आए थे तब डॉक्टर पवन कुमार ने उनसे नौकरी के लिए फिट करने को लेकर ?600 लिए थे।

व्यवस्था सुधारने के लिए सीएमओ का तबादला जरूरी

विधायक सोहन वाल्मीक ने महाप्रबंधक से कहा कि केंद्रीय चिकित्सालय की सीएमओ के द्वारा लगातार तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है जिनकी लगातार शिकायत हो रही है। चिकित्सालय की व्यवस्था सुधारने के लिए सीएमओ जय श्री राय का तत्काल तबादला करना जरूरी हो गया है।

मृतक का हार्ट हो गया था कमजोर

विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर पवन कुमार एवं डॉक्टर अक्षय बात करने के लिए पहुंचे। यहां पर डॉक्टर पवन कुमार ने विधायक एवं मृतक की पत्नी से बात करते हुए बताया कि अशोक डेहरिया का हार्ट काफी कमजोर हो गया था और वे काम नहीं कर सकते थे।इसलिए उन्होंने उन्हें नौकरी के लिए फिट नहीं किया था।उन्हें अपेक्स बोर्ड में आवेदन देने एवं इलाज के दस्तावेज देने को कहा गया था।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क में बनवाई घटिया सड़क

महाप्रबंधक और सहायक प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग

छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा, मध्यप्रदेश ङ्क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अमरवाड़ा ब्लॉक में बन रही सड़क में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। ग्राम पलटवाड़ा से सिंगोड़ी मार्ग के निर्माण में ठेकेदार वीरेंद्र सिंह राजपूत की लापरवाही और महाप्रबंधक कविता पटवा की निष्क्रियता को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहां कहां खराब है निर्माण चेनेज 0 मीटर से 159 मीटर तक बनी सीसी रोड टूट चुकी है।चेनेज 7250 से 11500 मीटर तक शोल्डर की स्थिति बेहद खराब है।चेनेज 650 से 8575 मीटर तक बीटी सर्फेस में सील कोट घटिया है।चेनेज 13900 मीटर पर ड्डष्ट्रङ्ख में रू30 ग्रेड की वायरिंग कोड की गुणवत्ता बेहद खराब है।सड़क सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया गया है।

जबलपुर में 12 वीं स्टेट शूटिंग चैम्पीयनशिप में....

छिंदवाड़ा के शूटरों ने मेडल जीता, साधा निशाना

छिंदवाड़ा। हाल ही में जबलपुर में स्थित गन फॉर ग्लोरी शूटिंग रेंज पर 16 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2025 तक 12 वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें छिंदवाड़ा के चंदनगांव भरतादेव रोड़ पर स्थित अर्जुन शूटिंग एकेडमी पर प्रशिक्षण ले रहे कुल 25 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, संस्था के सेक्रेटरी रामकृष्ण (शिवम) बरकोरिया ने जानकारी दी कि, एयर रायफल इवेन्ट मेन केटेगरी से शूटर योग्य पाटोदी ने एक सिल्वर, दो ब्रान्ज मेडल जीता एवं एयर पिस्टल जूनियर बूमेन टीम इवेन्ट से वैदेही भोयरकर, साक्षी बरकोरिया, वैष्णवी यादव ने ब्रान्ज मेडल जीता और ओपन इण्डिया शूटिंग चैम्पियनशिप में सौरभ पटेल ने 0.22 मेन केटेगरी से गोल्ड मेडल जीता एवं वहीं स्टेट में एयर रायफल बूमेन इवेन्ट से काजल प्रजापति चतुर्थ रेंक, कृतिका पाटिल आठवीं रेंक एवं हर्षी टाण्डेकर, अविरल ठाकुर, एयर रायफल मेन इवेन्ट से राजवीर रजक, कुणाल वैष्णव, अरिहंत सिंग, शम्स आजमी, अंतरिक्ष बर्मन, लक्ष्य डेहरिया, सिद्धार्थ डेहरिया, एयर पिस्टल मेन इवेन्ट आदित्य पतिंगे, शिवांश रघुवंशी, वैभव बंसोड़, क्रिश श्रीवास्तव, पार्थ वर्मा, रेषभ बाबरिया, रूपेश भादे, मीनाक्षी सिंग ने जोन एवं ओपन इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप के लिए सभी बच्चों ने क्वालिफाइड किया है खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर संस्था के अध्यक्ष प्रणय बोन्डे एवं उपाध्यक्ष सुनील वानखड़े ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा हम भविष्य में भी और अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करके उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल लाने के लिए प्रेरित करेंगे और आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी।

जिले में अभी तक 495.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज

छिन्दवाड़ा। जिले की औसत वर्षा 1059 मि.मी. है तथा जिले में अभी तक 495.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 535.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 24 जुलाई 2025 को प्रात- 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 24.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 24 जुलाई 2025 को प्रात-8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान तहसील छिंदवाड़ा में 64.8, मोहखेड़ में 7.3, तामिया में 23, अमरवाड़ा में 6.2, चौरई में 35, बिछुआ में 9.8, परासिया में 25.2, जुन्नारदेव में 29.8, चांद में 50.2 और उमरेठ में 22.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

हरे राम हरे कृष्ण का भजन

छिंदवाड़ा। इस्कान द्वारा गांधी गंज के व्यापारी केशव साहू के निवास पर हरे राम हरे कृष्णा का भजन किया गया, जिसमें इस्कान के पदाधिकारी एवं व्यापारी मित्रों ने भाग लिया।

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर...

सुकन्या समृध्दि खाता योजना हेतु सुकन्या रक्षा अभियान का आयोजन आज से 30 सितंबर तक

छिन्दवाड़ा। अधीक्षक डाकघर छिंदवाड़ा जितेन्द्र कुमार कावड़े ने बताया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा बालिकाओं को समाज में गरिमापूर्ण एवं आर्थिक रूप से समृद्ध स्थान प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रारंभ की गई अत्यंत लाभकारी योजना सुकन्या समृद्धि खाता को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिये निरंतर अथक प्रयास किये जा रहे है। जिसका मूल उद्देश्य यह है कि किसी भी बालिका के अभिभावक, अपनी बालिका के भविष्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने से वंचित न रहने पाये। इसी क्रम में मध्यप्रदेश डाक परिमंडल भोपाल के द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश में 25 जुलाई से 30 सितंबर तक रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर सुकन्या रक्षा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान पात्र सुकन्याओं की समृद्धि के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के अधिकाधिक खाते खोलने व इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से आयोजित किये जा रहे हैं। अधीक्षक डाकघर छिंदवाड़ा श्री कावड़े द्वारा जनमानस से अपील की गई है कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर बहन को उपहार के तौर पर सुकन्या समृद्धि खाता खोलकर उनके भविष्य को सुरक्षित करें।

गिफ्ट अ डेस्क पहल में सहभागिता कर दानदाता अवधेश बघेल ने 13 स्कूलों को भेंट की 192 डेस्क बेंच

प्राथमिक शाला दरासीकला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं कलेक्टर , स्कूली बच्चों के प्रति कलेक्टर संस्कृति जैन की सोच को मिल रही सराहना

सिवनी। जिला प्रशासन की ÷गिफ्ट अ डेस्क÷ मुहिम में जिले के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय भागीदारी निभाकर शासकीय विद्यालयों के सुविधाओं के उन्नयन का जिम्मा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में नागरिकगण शासकीय स्कूलों में अध्यनरत बच्चों के लिए डेस्क गिफ्ट कर बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन की इस अभिनव पहल में सहभागिता कर श्री अवधेश बघेल ने कुरई ब्लॉक के 13 स?कूलो मे 192 डेस्क बेंच प्रदान की गई है।

गुरूवार 24 जुलाई को प्राथमिक शाला दरासीकला में आयोजित हुए कार्यक्रम में कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन एवं दानदाता अवधेश बघेल ने अध्यनरत बच्चों एवं उनके परिजनों से संवाद किया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष लोचन सिंह मर्सकोले, उपाध्यक्ष हरदीप सिंह भाटिया, एसडीएम प्रशांत उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी-कर्मचारियों की भी उपस्थिति रही।

कलेक्टर सुश्री जैन ने अपने उद्बोधन में गिफ्ट अ डेस्क पहल के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढाने के लिए स्कूलों के बेहतर वातावरण एवं सुविधाओं के उन्नयन की भावना से गिफ्ट अ डेस्क अभियान चलाया जा रहा है। यह जिला प्रशासन का जन सहयोग से संयुक्त प्रयास है कि जिले की प्रत्येक प्राथमिक शाला में बच्चों के लिए डेस्क उपलब्ध हो। उन्होंने बताया कि इस मुहिम में बढ-चढकर जिलेवासी सहयोग कर रहे हैं।

कलेक्टर जैन ने अपने लिए डेस्क-बैंच पाकर उत्साहित बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के साथ ही ग्रामीण जनों अपने ग्राम के स्कूल एवं उनमें अध्ययन करने वाले बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों के माता-पिता के साथ ही ग्रामवासियों का यह दायित्व है कि ग्राम का बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाये। स्कूल में बेहतर पढाई हो तथा स्कूल में जो पढाया जा रहा है वो बच्चे के समझ में आए। उन्होंने कहा कि गांव का भविष्य हम सब की जिम्मेदारी है। जिसके लिए हमें आज अपने बच्चों पर मेहनत करने की जरूरत है ताकि बड़े होकर बच्चे आपका, आपके ग्राम तथा ग्राम की खुशहाली की जिम्मेदारी लेने के लायक बन सके। शिक्षा से जीवन में बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं।

कलेक्टर जैन ने कहा कि आज जो व्यक्ति बेहतर स्थिति में है वह उसकी शिक्षा से ही संभव हो सका है। उन्होंने बच्चों से कहा कि सभी जी जान से पढाई कर ध्यान दें और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर सुश्री जैन ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की ओर से दानदाता अवधेश बघेल का आभार पत्र भेंट किया।

शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नपा अधिकारी से मिला भाकपा का प्रतिनिधि मंडल

सिवनी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सिवनी शहर की जन समस्याओं को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मिला और बरसात के समय में शहर के विभिन्न निचले क्षेत्र में भर रहे पानी की निकासी, शहर की नालियों से निकाले गए कीचड़ और अवशिष्ट को शीघ्र उठाकर यथा स्थान रखना, विवेकानंद वार्ड के लड़इयां मोहल्ला से पानी और गंदगी को साफ करने, आवारा पशुओं को हाका गैंग से कांजी हाउस ले जाने, भगत सिंह वार्ड नहर क्षेत्र के पानी को कर्वे कॉलोनी आने से रोकने, भगत सिंह वार्ड के विभिन्न स्थानों के कीचड़ युक्त क्षेत्र से पानी की निकासी करने, दलसागर तालाब नहर हेड के पास मुरूम डलवाने, सुलभ शौचालय पेट्रोल पंप के पास से कचरे के ढेर को अलग करने, आदि आदि समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओमप्रकाश बोर्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कॉमरेड डी डी वासनिक कामरेड किरण प्रकाश और धनीराम बंडेवार शामिल थे ने चर्चा की जिस पर नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इन समस्याओं को शीघ्र दूर करने की बात की। सिवनी नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इन समस्याओं को शीघ्र दूर करने की बात की यदि समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो समस्या ग्रस्त जनता नगर पालिका सिवनी के कार्यालय के सामने धरना देने के लिए बाध्य होगी।

हरियाली की चादर से यातायात पार्क खिला

भोपाल। बारिश के मौसम ने हर तरफ हरियाली की चादर बिछा दी है। इस हरियाली की चादर से यातायात पार्क भी खिल उठा है।

घोषणाओं को पूर्ण कराने के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा

भोपाल। आज ठेकड़ी भवन में मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई इस पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के महामंत्री देवेंद्र उपाध्याय ने बताया की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में पूर्ण करने हेतु चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा समय-समय पर विधायक को सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो सरकार के खिलाफ अपनी मांगे मनवाने हेतु उग्र आंदोलन किया जाएगा।

भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित

भोपाल। भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक, डॉ हेडगेवार स्मृति मंदिर/परिसर, रेशिमबाग नागपुर में हुई। अखिल भारतीय अध्यक्ष के साई रेड्डी, महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख व किसान संघ के संपर्क अधिकारी रामलाल जी मंच पर उपस्थित रहे।

केबल स्टे ब्रिज मामले को लेकर आलोक शर्मा मिले गडकरी से

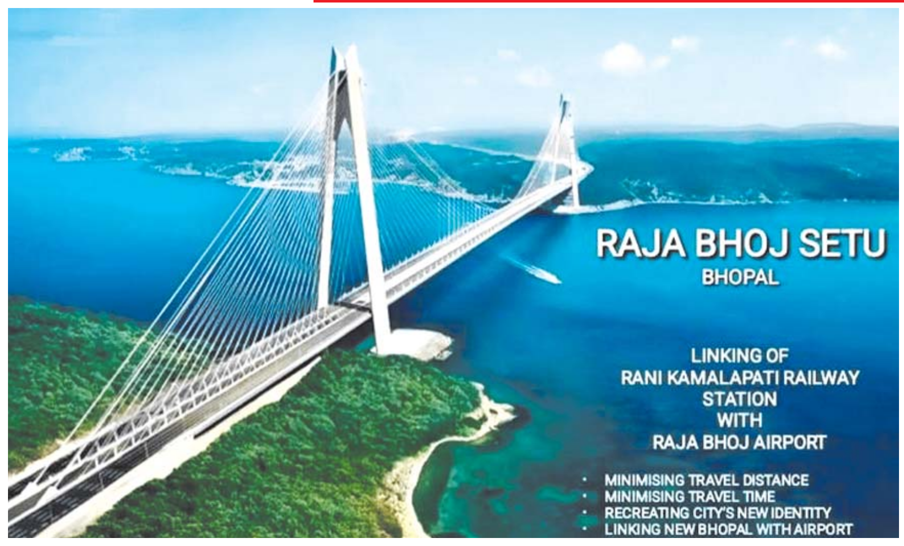

भोपाल में बड़े तालाब के ऊपर से 17 किलोमीटर मार्ग, जिसमें एलिवेटेड 2 किलोमीटर मार्ग का राजाभोज सेतु के नाम से केबल स्टे ब्रिज बनाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सांसद आलोक शर्मा ने भेंट की। गडकरी ने डीपीआर देखने के बाद कहा कि भोपाल में इसकी जरूरत है। इससे भोपाल के विकास को पंख लगेंगे।

सीएम मोहन यादव लाड़ली बहना को रक्षाबंधन के पहले देंगे दो सौगात

भोपाल। रक्षाबंधन 2025 के अवसर पर मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों को मुख्यमंत्री मोहन यादव से दो विशेष सौगातें मिलेंगी। इसके अलावा, रेलवे यात्रियों के लिए भी एक खास सुविधा दी जा रही है। इस बार रक्षाबंधन भद्रा के बिना मनाया जाएगा, जिससे बहनें पूरे दिन राखी बांध सकेंगी। रक्षाबंधन एक विशेष पर्व है जो भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक है। इस बार, रक्षाबंधन 9 अगस्त को पूरे देश में मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन 2025 की खुशियां मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए और भी खास होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बार लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को अतिरिक्त लाभ देंगे। इसके साथ ही रेलवे द्वारा भी यात्रियों के लिए खास सौगात दी जा रही है।

रेलवे ने दी यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन- रक्षाबंधन 2025 के मौके पर मध्यप्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए भी एक खास सौगात दी जा रही है। पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल और इंदौर के बीच तेजस सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह पहली बार है जब मध्यप्रदेश में तेजस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन यात्रियों के लिए यात्रा को और भी आसान बनाएगी।

9 अगस्त से पहले मिलेंगे 1500 रुपए

सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना के तहत 1250 रुपये की मासिक राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा की है। यह राशि राखी के मौके पर बहनों को दी जाएगी। इस राशि का ट्रांसफर अपने तय समय से पहले 9 अगस्त से पहले कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश की लाखों बहनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ेगी।

29 अगस्त तक चलेगी इंदौर मुंबई तेजस ट्रेन

इंदौर-मुंबई तेजस स्पेशल ट्रेन 29 अगस्त 2025 तक चलेगी। ट्रेन संख्या 09085 (मुंबई सेंट्रल-इंदौर) सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 11.20 बजे मुंबई से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचेगी। दूसरी ओर, ट्रेन संख्या 09086 (इंदौर-मुंबई सेंट्रल) मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 5 बजे इंदौर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7.10 बजे मुंबई पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

यह ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें बोरिवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम और उज्जैन शामिल हैं। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर और एसी 3-टियर कोच होंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

नहीं होगा भद्रा का साया

रक्षाबंधन 2025 में इस बार भद्रा का साया नहीं रहेगा। इससे पहले के वर्षों में भद्रा के कारण बहनों को राखी बांधने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन इस बार पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ रहेगा, जिससे बहनें अपने भाइयों को पूरे दिन राखी बांध सकेंगी। पिछले तीन सालों में भद्रा के कारण राखी बांधने में परेशानी हुई थी, लेकिन इस साल सब कुछ आसान होगा।

पर्यटन कॉन्क्लेव से विन्ध्य में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा - उप मुख्यमंत्री शुक्ल

विन्ध्य की पर्यटन संभावनाओं को अवसर में बदलेगा कॉन्क्लेव

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन सर्किट हाउस रीवा में 26 और 27 जुलाई को रीवा में आयोजित पर्यटन कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि कॉन्क्लेव में विन्ध्य के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों तथा पर्यटन स्थलों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पर्यटन से जुड़े होटल उद्योग, वाहन उद्योग, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संगठन, टूर आपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड आदि भी इसमें शिरकत करेंगे। पर्यटन के विकास से विन्ध्य में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। कॉन्क्लेव में दूसरे दिन पर्यटन के विकास से जुड़े विभिन्न आयामों पर विचार मंथन किया जाएगा। इसमें कालेज के पर्यटन विभाग के प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों को भी शामिल करें। कॉन्क्लेव में 500 से अधिक डेलिगेट्स रीवा आ रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था करें कि इनके मन में स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक रीवा की छवि इनके साथ जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नगर की साज-सज्जा के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र में सुरम्य प्राकृतिक स्थल, मनोहारी जलप्रपात, भव्य मंदिर और ऐतिहासिक इमारते हैं। विन्ध्य में कई टाईगर रिजर्व और अभ्यारण्य पर्यटन के बड़े केन्द्र हैं। यहाँ की प्रचुर वन संपदा, नदियाँ और अन्य प्राकृतिक स्थल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विन्ध्य में मैहर में माँ शारदा माता का मंदिर, चित्रकूट धाम, देवतालाब और रीवा के शिव मंदिर लाखों लोगों की आस्था के केन्द्र हैं। आज विन्ध्य में चारों ओर फोरलेन सड़कें, रेलवे और हवाई सेवा की उपलब्धता है। अच्छे होटलों का तेजी से विकास हो रहा है। विन्ध्य शीघ्र ही पर्यटन में तेजी से विकास करेगा। रीवा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 26 जुलाई को पर्यटन कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। यह दो दिवसीय पर्यटन कॉन्क्लेव विन्ध्य में पर्यटन को नया आयाम देगी।

चुनाव आयोग ने बीएलओ का मानदेय किया दोगुना:अब एक साल में 12 हजार रुपए मिलेंगे, स्पेशल ड्राइव का इंसेंटिव अलग से मिलेगा

भोपाल। बिहार चुनाव के पहले भारत निर्वाचन आयोग ने देशभर में चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) की प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है। एमपी में काम करने वाले बीएलओ को प्रोत्साहन के रूप में मिलने वाली यह मानदेय राशि अब दोगुनी हो गई है। अभी तक इन्हें छह हजार रुपए मिला करते थे और अब आयोग के फैसले के बाद 12 हजार रुपए मिलेंगे।

चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को इसके आदेश जारी कर देश के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इसके आधार पर भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अफसरों के अनुसार चुनाव आयोग का मानदेय बढ़ाने संबंधी आदेश एमपी को भी मिला है और इसके लिए नोटशीट जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर बूथ लेवल अफसर और सुपरवाइजर को बढ़ा हुआ मानदेय दिए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि देश के अलग-अलग राज्यों में बीएलओ को अलग-अलग मानदेय दिया जाता है। एमपी में कम राशि मिल रही थी। अब नए निर्देश के बाद इन्हें हर महीने एक हजार रुपए के हिसाब से मानदेय मिलने लगेगा। पहले यह 500 रुपए महीने के हिसाब से मिल रहा था।

अब ऐसे मिलेगा बीएलओ सुपरवाइजर को मानदेय

- बीएलओ को अभी तक एमपी में 6 हजार रुपए मिलते थे और चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब 12 हजार रुपए सालभर में मिलेंगे।
- सुपरवाइजर को अभी तक 12 हजार रुपए मिलते थे और अब नए निर्देश के बाद इन्हें सालभर में 18 हजार रुपए मिलेंगे।
- चुनाव आयोग ने इसके साथ ही चुनाव कार्य करने वाले बीएलओ को स्पेशल ड्राइव चलाने पर 2000 रुपए इंसेंटिव देने का भी फैसला किया है।

नशे से दूरी- है जरूरी ज़न जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल अवधेश गोस्वामी एवं पुलिस उपायुक्त जोन - 03 भोपाल रियाज इकबाल के निर्देशन मे नशा मुक्ति अभियान के तहत जोन-03 के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महोदय ,हनुमानगंज,कोतवाली,शाहजहाँनाबाद संभाग के सहायक पुलिस आयुक्त एवं समस्त थाना प्रभारी एवं थाना स्टाफ रहा मौजूद।

इंदौर एडिशनल डीसीपी की पत्रकार से बदसलूकी का मामला, राज्य मंत्री जायसवाल ने कहा- कार्रवाई होगी

जबलपुर। पत्रकार हेमंत शर्मा से पुलिस अधिकारी द्वारा बदतमीजी और अभद्रता पर राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि निश्चिंत रहिए इस पर कार्रवाई जरूर होगी। कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बदसलूकी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, न हीं सरकार इस बात की इजाजत देती है। हर किसी के साथ बहुत अच्छे से वार्ता करनी चाहिए। वहीं कार्रवाई वाले सवाल पर कहा कि भरोसा रखिए कार्रवाई जरूर होगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक हत्या के मामले में सवाल पूछने पर एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने मीडियाकर्मियों के माइक आईडी पर हाथ मारते हुए कहा था कि तुम्हारी औकात क्या है? इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद आलोक शर्मा को जमकर ट्रोल भी किया गया।